कामरेड पी० राममूर्ति द्वारा प्रस्तुत

महासचिव की रिपोर्ट

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

तृतीय वार्षिक सम्मेलन

२१ से २५ मई, १९७५ / सन्मुखानंद हाल, बम्बई

एम० के० पन्धे द्वारा सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए
१७२, लेनिन सरणी, कलकत्ता-७०००१२ से प्रकाशित तथा
प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, १, लारेंस रोड, दिल्ली-३५ से मुद्रित

साथियो,

हमारे अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में गहरे होते जा रहे आर्थिक संकट के फलस्वरूप देश की मेहनतकश जनता के जीवन में बढ़ती जा रही तकलीफों और उनको जन्म देने वाली सरकारी नीतियों का जिक्र किया है। इसलिए इस रिपोर्ट में मैं उन सबकों का जिक्र करना चाहता हूं जो दूसरी कांग्रेस के बाद हमें मिले हैं।

संयुक्त आंदोलनात्मक कार्रवाई और संयुक्त संघर्ष के लिए एकता की नीति, जो पिछले दिनों में अपनाई गई, के बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं। अब एक ऐसा मौका हमारे सामने आया है जब हम संघर्ष के दौर में उसके चरित्र एवं स्वरूप के अन्दर आए परिवर्तनों को अच्छी तरह समझलें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक एक संयुक्त प्रतिरोध-संघर्ष के निर्माण की दिशा में हमारे सारे प्रयास अधूरे ही कहे जाएँगे।

यह एक तथ्य है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में, बीस लाख से भी अधिक मजदूरों ने हड़तालें और संघर्ष किए हैं। इस प्रकार के लम्बे संघर्षों में दूसरे जनसमूहों के मुकाबले मजदूर वर्ग और कर्मचारियों ने ही सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है। एकता और संयुक्त सघर्षों के विकास के कारण इस प्रकार के संघर्षों का प्रभाव और व्याप्ति बहुत अधिक बढ़ी है।

संकट के विरुद्ध संघर्ष

स्थानीय संघर्ष प्रायः अब उद्योगों के हिसाब से समूचे राज्य-व्यापी संघर्षों में बदल जाते हैं। आजकल इस प्रकार के राज्यव्यापी संघर्ष और प्रतिरोध-कार्रवाइयां आम बात होती जा रही हैं।

इसी सिलसिले में, अखिल भारतीय स्तर पर भी प्रतिरोध कार्रवाइयों का आह्वान किया जाता रहा है, जिसमें मजदूरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अखिल भारतीय स्तर पर चलने वाली लंबी रेल हड़ताल और उससे भी पहले चटकल मजदूरों की हड़ताल इसी सिलसिले की कड़ियां हैं।

इन संघर्षों के फलस्वरूप विकसित होने वाले एकजुटता के अहसास और आत्मविश्वास ने हमारी ट्रेड यूनियनों के कार्यक्षेत्र और कार्यभारों को और भी बढ़ा दिया है।

वर्तमान आर्थिक स्थिति के विकास और उसके खिलाफ संघर्ष के दौरान हमारे संघर्षों के स्वरूप में पर्याप्त बदलाव दिखाई देता है। किसी एक खास उद्योग के किसी एक हिस्से की तनुख़ाह, बोनस या डी० ए० इत्यादि जैसे फौरी मसलों के गिर्द उभरने वाले संघर्ष अब एक आम संघर्ष में ऐसी मांगों को भी प्रायः समेट लेते हैं जो न केवल मजदूरों के हितों से ही संबद्ध होती हैं, बल्कि समाज के दूसरे हिस्सों के हितों से भी जुड़ी हुई होती हैं। चढ़ती कीमतों को रोकने, खाद्यान्न और राशन की सही व्यवस्था करने, वेतन जाम खत्म करने और आवश्यकता पर आधारित वेतन की मांग करना इत्यादि ऐसी ही मांगें हैं। वास्तव में यह प्रक्रिया अब समूचे मजदूर वर्ग और समाज पर डाले गए संकट के खिलाफ दिन प्रतिदिन एक आम-संघर्ष का रूप धारण करती जा रही है।

किन्तु, इस सबके बावजूद, मजदूर वर्ग एवं अन्य दूसरे संघर्ष-रत तबकों में अपनी लड़ाइयों को किसी खास मांग तक ही महदूद समझने की प्रवृति आज दिखलाई पड़ती है। सरकार की वर्तमान नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने और विकल्प की नीतियों के लिए संघर्ष करने की समझ अभी भी उनकी चेतना का अंग नहीं बन पाई है।

सभी की हिस्सेदारी

वर्तमान संकट के कारण शहरी मेहनतकश जनता के सभी तबके अब मैदान में उतरने लगे हैं। कर्मचारी—चाहे वे केन्द्रीय सरकार के मातहत काम करते हों या राज्य सरकारों के मातहत, जीवन बीमा निगम के हों या मर्केंटाइल के, पेशेवराना तबके के हों या वेतन पर निर्भर रहने वाले अधिकारी-कर्मचारी, अध्यापक हों या प्रोफेसर—सभी या तो अपनी मांगों को लेकर मैदान में आने

लगे हैं या प्रतिरोध-कार्रवाइयों के लिए अखाड़े में उतरने लगे हैं। उनके साथ साथ अब कामगार महिलाएँ एवं गृहणियां भी सामने आने लगी हैं। आज मजदूर वर्ग द्वारा छेड़ा गया कोई भी संघर्ष शहरों में रहने वाले सभी मेहनतकश तबकों के आम संघर्ष में तब्दील हो जाता है।

इन संयुक्त आन्दोलनों के उग्र और वामपंथी चरित्र को इस तरह से देखा जा सकता है कि आज आन्दोलनरत मजदूर वर्ग और संघर्षकारी जनता अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष एवं विदेशी पूंजी और इजारेदारियों के राष्ट्रीयकरण की मांगों को अपना सहज समर्थन प्रदान करने लगी है। संयुक्त कार्रवाइयों की भावना और आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है और अब यह प्रवृति सिर्फ कुछेक केन्द्रीय संगठनों के आह्वान तक ही महदूद नहीं रहती। जिन राज्यों या इलाकों में कोई केन्द्रीय संगठन या उससे संबद्ध संगठन अस्तित्व नहीं रखता, वहां पर भी जनता में संघर्षकारी पहलकदमी की भावना और आन्दोलन विकसित हो जाते हैं। ये संघर्ष सिर्फ उन्हीं संगठनों को नहीं समेटते जो किसी न किसी केन्द्रीय संगठन से संबद्ध हैं, अपितु ऐसे संगठनों, फैडरेशनों को भी अपने साथ खींच लाते हैं जो किसी भी केन्द्रीय संगठन से संबद्ध नहीं होते।

एन० सी० सी० आर० एस० (नेशनल को-आर्डिनेशन कमेटी आफ रेलवे सर्विसमैन) और वेतन जाम विरोधी राष्ट्रीय अभियान समिति इसी प्रकार की संयुक्त कार्रवाइयों के नाम पर दो महत्वपूर्ण मिसालों के रूप में हमारे सामने आती हैं।

एकजुटता के प्रति ऐसा उत्साह वास्तव में एक ओर लगातार बिगड़ती जा रही आर्थिक स्थितियों एवं दूसरी ओर मजदूरों के द्वारा लगातार अनुभव की जा रही एकता की आवश्यकता का ही परिणाम है जिससे हमारे समाज की वर्ग स्थिति के बारे में हमारी नीति की सच्चाई ही सिद्ध होती है। सरकार और मालिकों द्वारा किए जाते हमलों के बढ़ाव के कारण, मेहनतकश वर्ग की एकजुटता की जरूरत को दिनोंदिन ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है।

स्वतंत्र आंदोलनात्मक कार्रवाई

इन संयुक्त संघर्षों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इनमें से ज्यादातर संघर्षों को भयानक दमन का सामना करना पड़ा है। चाहे

स्थानीय स्तर के संघर्ष हों चाहे राजसत्ता के या अखिल-भारतीय स्तर के संघर्ष हों—अब तो मजदूर को सभी प्रकार की नागरिक आजादी और उसके जनवादी अधिकारों को भयंकर हमलों और निरंकुश दमन-उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। संघर्षों का यह पहलू उन्हें एक प्रकार की उग्र राजनीतिक धार प्रदान कर देता है जो आर्थिक या सीमित स्थानीय मांगों के सीमित क्षेत्र से बाहर व्यापक क्षेत्र में खींच लाता है।

हमें मिली सफलताओं का आधारभूत कारण वास्तव में हमारी ट्रेड यूनियन की स्वतंत्र आंदोलनात्मक कार्रवाइयाँ करने, जनता के बीच सीधे पहुंचने और उसे संघर्ष में खींच सकने की क्षमता में निहित है। अगर ऐसा न होता तो सुधारवादी और संशोधनवादी नेता अपने संघर्ष-विरोधी रुखों को आसानी से नहीं बदलते। ऐसा तभी संभव हुआ है जब एक ओर नेतृत्व के स्तर पर ऊपर से एकता की अपीलें की जाती रही हैं और दूसरी ओर नीचे आधार क्षेत्र में, जड़ में भी लगातार काम किया जाता रहा है। जहाँ नीचे के काम की उपेक्षा बढ़ती गई है वहां या तो संयुक्त कार्रवाई संभव ही नहीं हो पाई है या फिर वह नितांत औपचारिक एवं नाम मात्र की रह गई है। कुछ संयुक्त संघर्षों के दौरान हम किसानों की मांगों को भी औपचारिक रूप में उठाने में सफल रहे हैं। पिछले वर्ष और इस वर्ष की चटकल (जूट) हड़तालों में जूट-उत्पादकों के लिए अच्छे दाम दिलाने और जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग को हमारे द्वारा उठाया गया और लोकप्रिय बनाया गया है। महाराष्ट्र में मई १९७३ में हुई हड़ताल के दौरान लाखों लाख मजदूर अकाल की गिरफ़्त में आए हुए किसानों के समर्थन में निकल पड़े और उन्होंने १३ लाख खेत मजदूरों को, अकाल से राहत दिलाने के लिए अगले ही दिन हड़ताल पर जाने में मदद दी।

ढुलमुल यकीन रवैया

संघर्षों के वर्तमान स्वरूप का एक विशेष पहलू एटक (ए० आई० टी० यू० सी०) के संशोधनवादी एवं इंटक (आई० एन० टी० यू० सी०) के नेतृत्व के आमतौर पर ढुलमुल यकीन रवैया और एक रुख से दूसरे रूख के बीच झूलते रहने के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन संयुक्त आंदोलनात्मक कार्रवाईयों के लिए जनता का उत्साह

और बेकली सरकार द्वारा पैदा किए गए परम्परागत अवरोधों और सुधारवादियों द्वारा मजदूरवर्ग में फूट डालने की पुरानी तिकड़मों को तहस नहस कर डालता है। फिर भी, जब संघर्ष समाप्त हो जाता है या कोई समझौता हो जाता है तो इस दौरान इनके अवरोधों के दबाव काफी हद तक बरकरार रहते हैं। इन संघर्षों का खुले तौर पर विरोध करने में असमर्थ ये लोग कुटिलचालें चलने और इन संघर्षों के भीतर घात करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी गद्दारी के कारण किसी संघर्ष के वापस हो जाने या पराजित हो जाने के बाद भी इनका प्रभाव बना रहता है।

खासकर **एटक** के नेताओं का ढुलमुलपन एक ओर दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के रुख के बदलाव और दूसरी ओर मजदूरों के द्वारा डाले जाते दबाव की मात्रा पर निर्भर करता है। **इंटक** के नेता लोग अपने दल (कांग्रेस) की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों से अधिकाधिक बंधते चले जा रहे हैं और उनका दल प्रायः उनसे मजदूरों से टकराने की नीति अपनाने का आग्रह करता है। तब भी दबाव के कारण इनके नेतृत्व में चलने वाली स्थानीय यूनियनें, यूनिटें और छोटे नेता-कार्यकर्त्ता ऐसे आदेशों की जंज़ीरो को तोड़ फेंकते हैं और संघर्षों में शामिल होते हैं।

हिं० म० सं० (हिन्दुस्तान मजदूर संघ या एच० एम० एस०) संयुक्त कार्रवाईयों में स्थानीय स्तर पर शामिल होते हैं जैसे कि बंबई में, किंतु इसकी मुख्य संगठन क्षमता संयुक्त कार्रवाईयों से प्रायः बाहर ही बनी रहती है। हालांकि ए० आई० आर० एफ० (आल इंडिया रेलवे मैंस फैडरेशन) ने रेल हड़ताल की पहलकदमी की और एक राष्ट्रीय अभियान समिति भी बनाई। यह **हिं० म० सं०** की ही एक घटक इकाई है।

'दूषित' या 'अपवित्र' हो जाने का खतरा

हमारा मित्र संठगन **उक्टू** (यूनाइटेड कांउसिल आफ ट्रेड यूनियन या यू० सी० टी० यू०) संयुक्त संघर्षों के दौरान चाहे कम या ज्यादा किन्तु प्रायः सक्रिय रहा है। हमारे साथ साथ यह संगठन संयुक्त संघर्षों के प्रायः केन्द्र में रहता है। फिर भी, संयुक्त जनसंघर्षों में हम अक्सर यह पाते हैं कि हमारे मित्र संगठन जन प्रदर्शनों और मीटिंगों के स्तर पर अपनी समूची ताकत नहीं लगाते। बंबई,

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में यह अक्सर देखा गया है कि मीटिंगों में आने वाली और संबोधित की जाने वाली जनता का प्रमुख हिस्सा सीआईटीयू के इर्द गिर्द वाला ही होता है। ऐसा लगता रहा है कि दूसरे संगठन अपनी जनता को इन आम मीटिंगों में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं करते। वास्तव में इस तरह के संगठनों के कुछेक नेताओं के दिमाग में, वैचारिक प्रभाव में आकर 'दूषित' या 'अपवित्र' हो जाने,एकता की भावना विकसित होने और इस दिशा में आने वाले अवरोधों के तहस नहस होते जाने का डर हावी हो गया लगता है। ऐसा रवैया संयुक्त संघर्षों के निर्माण एवं उनके बरकरार रहने में दिक्कतें पैदा करता है। फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हालांकि आम मीटिंगों और प्रदर्शनों के लिए **उक्टू** (यू सी टी यू) आदि हमारे मित्र संगठन अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते, फिर भी वे संयुक्त कार्रवाइयों और बन्द इत्यादि में अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं।

इस सिलसिले में हमारी शिकायत सबसे पहिले **एटक** के नेताओं से है। वे अक्सर औपचारिक तौर पर हमारे साथ साथ बने रहते हैं। वे आम जलसों में भाषण देते तो आ जाते हैं, किन्तु उनमें अपनी जनता को नहीं लाते। वास्तव में इस प्रकार का रवैया उनके इस नजरिए का सीधा परिणाम है, जो संयुक्त संघर्षों को एक ऐसी बुराई की तरह समझना है जिससे पिन्ड नहीं छुडाया जा सकता। पिछले ही दिनों दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की विजयवाड़ा कांग्रेस के प्रस्ताव के मुताबिक **एटक** नेताओं ने भी अब खुले तौर पर संघर्ष विरोधी रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है।

हमें अपना काम ऐसी ही जटिल स्थितियों में आगे बढ़ाना होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि हमने बदलती हुई जरूरतों को हमेशा ही समझा है और संघर्ष-विरोधियों के इरादों को जबाबी कार्रवाइयों से ध्वस्त कर दिया है।

गलतियां

इन दिनों जब तमाम मेहनतकश जनता संघर्षों में निरंतर जूझ रही है, जब उसका स्वतःस्फूर्त आक्रोश और वर्तमान संकट का कशाघात लाखों लाख लोगों को आंदोलन में खींच रहा है, तब हमसे दो प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं। स्वयं की ताकत को ज्यादह

कूत लेना और एकता के लिए किए जाने वाले संघर्ष की उपेक्षा करना और नतीजतन स्वयं को बार-बार मुसीबतों में फंसा हुआ पाना या फिर आन्दोलन के उभार को कम कर बैठना—पहली प्रकार की गलती है। मसलन १९७४ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के आह्वान के संदर्भ में ऐसा ही हुआ था। नीचे जनता में गहराते जा रहे असंतोष को भुलाकर सुधारवादी नेताओं की भलमनसाहत और मर्जी का जरूरत से ज्यादह इंतजार करते रहना—दूसरे प्रकार की गलती है। यह गलती संयुक्त संघर्ष की शक्ति को कम करते हुए हमारे अपने आधार क्षेत्र में हमारी स्वतंत्र कार्रवाई को ढीला कर देती है।

ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जहाँ हमारे कामरेड उकसावेबाज और भड़कावेबाजी के शिकार बने। कुछ ऐसे मौके आए हैं जब हमारे कामरेड उकसावेबाजी और भड़काने के बावजूद दृढ़ बने रहे हैं और एकता के लिए संघर्ष चला सके हैं। ये दानों प्रकार के मौके बंबई में देखने को मिले। १९७३ में गिरनी कामगार यूनियन के **एटक** के नेताओं ने हमसे कोई भी सलाह मशविरा किए बिना अचानक कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का आह्वान कर दिया। इससे भड़क कर हमने वहाँ एक गलत रुख अपना लिया जो बाद में हड़ताल के प्रति मजदूरों के अनुकूल रुख से और भी सिद्ध हो गया। एक और मौके पर, **हिंद मजदूर पंचायत** के नेता अचानक ही एक संयुक्त आह्वान से अलग हट गये। उन्होंने आंदोलन की एक दूसरी तारीख घोषित कर दी। इस पर हमारे कामरेडों ने सही रुख अपनाया और अपने मित्र संगठनों के साथ आह्वान को जारी रखा और बाद में पंचायत के आह्वान का भी समर्थन किया।

कभी-कभी ऐसे भी अवसर आते हैं कि हमारे साथी **इंटक** के सुधारवादी नेताओं की कूटचालों की मुकाबला करने में समर्थ नहीं होते और हम ऐसे मौके पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं जो हमारे मजदूरों के लिए अनुकूल नहीं होता। ऐसी हालत १९७५ में पश्चिम बंगाल की जूट हड़ताल के दौरान हमारे सामने आई।

अवरोधी स्थितियों की गैर जानकारी आंदोलन के लिए अनुकूल स्थिति के चुनाव के बारे में पहिले से ही मजदूरों को शिक्षित करने की असमर्थता सुधारवादियों की कूटचालों को रोकने में नाकामयाब बनाती है।

सयुक्त संघर्षों का, एक ही मंच से चलाये जाने वाले आंदोलनों का संचालन ही यह तै करता है कि उससे मजदूर, चेतना के स्तर पर किस हद तक लाभान्वित होंगें। कभी-कभी सुधारवादी नेता एक आम आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रतिक्रियावादी शर्तें भी लगाते हैं, कभी-कभी इन शर्तों को मानना भी पड़ जाता है। किन्तु उनके प्रति बहुत ही कम प्रतिरोधी रुख अपनाया जाता है और ऐसा यहां तक होता है कि हमारा प्रचारात्मक एवं आंदोलनात्मक रवैया दूसरों से भिन्न नहीं होता। कभी कभी आम मांगों का पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया जाता और सुधारवादियों की ही तरह कुछ फौरी आर्थिक मसलों पर ही सारा ध्यान लग जाता है। इससे भी आगे व्यापक प्रतिनिधित्ववादी हड़ताल समितियों को अपने संगठनों के साथ खींचे बिना और इस तरह से आम मजदूरों में नेतृत्व की क्षमता के विकास की संभावना को अवरुद्ध करते हुए प्रायः आंदोलनों का संचालन किया जाता है। हड़ताल का संचालन अक्सर कुछेक वरिष्ट नेताओं तक ही महदूद रह जाता है और नीचे की जनता को जन आंदोलनों के संचालन में कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती और न उसे नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए ही प्रेरित किया जाता है। यह कार्यविधि वास्तव में सुधारवादी और संशोधनवादी नेताओं के अनुकूल पड़ती है जो संघर्षों का नेतृत्व करने के लिए एक नौकरशाही ढ़ाँचे से ज्यादह किसी चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानते।

ये ही हमारी कुछेक कमियाँ और तजुर्बे हैं। इन्हें और भी ठोस रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए, इनका बिश्लेषण किया जाना चाहिए और इनसे सबक निकाले जाने चाहिए जिससे कि हम उन्हें दूर कर सकें। ऐसा किए बिना संघर्ष के नए दौर में नेतृत्व के लिए संगठनात्मक और वैचारिक जरूरतों को पूरा करनें में हम असमर्थ ही रहेंगे।

साथियो, इस सिलसिले में, मैं कुछेक महत्वपूर्ण हड़तालों का जिक्र सुनाना चाहता हूं जो राज्यव्यापी या देशव्यापी स्तर पर कई उद्योगों में पिछले दिनों चली हैं।

महाराष्ट्र की दो लाख सूती कपड़ा मजदूरों की हड़ताल, १९७४ के आरंभ में तामिलनाडु में डेढ़ लाख कपड़ा मजदूरों की हड़ताल, दिल्ली की कपड़ा मजदूरों की हड़ताल, तामिलनाडु की चीनी मिल मजदूरों की हड़ताल, केरल हरियाणा और पंजाब की राज्यव्यापी

बिजली मजदूरों की हड़तालें, १९७४ की अखिल भारतीय स्तर पर चटकल (जूट) मजदूरों की हड़ताल, १९७५ में दो लाख चटकल मजदूरों की हड़ताल, केरल में सड़क यातायात प्लांटेशन, कापर इत्यादि के मजदूरों का राज्यव्यापी संघर्ष-कुछ महत्वपूर्ण राज्यव्यापी संघर्षों के उदाहरण हैं। इस सबसे ऊपर अखिल भारतीय स्तर पर चली रेल मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल हमारे सामने है।

अब मैं इन संघर्षों में एकता कायम करने के दौरान आए विभिन्न तजुर्बों और उन तौर-तरीकों का जिक्र करूंगा, जिनके बीच होकर हमें काम करना पड़ा है।

दरअसल, एकता के लिए किए जाने वाले संघर्ष के अनेक रूप हमारे सामने आए हैं। कभी किसी एक दिन की कार्रवाई या किसी प्रदर्शन के लिए इस एकता के संघर्ष ने अभियान समिति का रूप लिया है तो कभी हजारों लाखों मजदूरों को समेटकर चलने वाली लंबी हड़तालों के संचालन के लिये संयुक्त समितियों या सलाह मण्डलों का रूप धारणा किया है। यह वहां भी संभव हुआ है जहां हम एक बड़ी शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। यह वहां भी संभव हुआ है जहां हम एक छोटी शक्ति के रूप में जाने जाते हैं।

रेलवे में हम एक छोटी सी शक्ति के रूप में थे, बड़ी-बड़ी यूनियनें आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन से सम्बद्ध हैं, (इसके अलावा इंडियन नेशनल रेलवे फैडरेशन और डांगे की आई० एफ० आर० भी है)। कुछेक स्वतंत्र हैं जैसे एल० आर० एस० ए० अथवा वे एक दूसरे संगठन कन्फ्रैडरेशन से सम्बद्ध हैं। ए० आई० आर० एफ० से अलग कुछ यूनियनें सीआईटीयू से सम्बद्ध हैं। हालांकि दूसरे संगठनों में ऐसे बहुत से नेता हैं जो हमारी एकता की नीति को पसंद करते हैं और उस पर चलते भी हैं।

इन हालात में एकता कायम करने की यह लड़ाई किस तरह से चलाई गई ? एनसीसीआरएस समिति का आखिरी दम तक समर्थन करते हुए, हम किस तरह से उस पर अपना प्रभाव छोड़ सके ? रेल मजदूरों के बीच सीआईटीयू ने किस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त की ?

रेल मजदूरों की तीन सप्ताह की रेल हड़ताल, भारत के मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना की तरह दर्ज है। यह पहली अखिल भारतीय रेल मजदूरों की हड़-ताल थी। उसके पहिले कभी इस तरह से, रेल मजदूरों ने अपने

संगठनों के आह्वान पर हड़ताल करने का फैसला नहीं किया। वह हड़ताल लगभग तीन सप्ताह चली जो कदाचित दुनियां में एक रिकार्ड है।

इस शक्तिशाली रेल हड़ताल की राजनीतिक सार्थकता यह है कि वह वामपंथी और जनवादी दलों के संयुक्त मोर्चे और उनके नेतृत्व में चलने वाले जन संगठनों के द्वारा ही संभव हुई थी।

यह इसलिए संभव हो सकी क्योंकि हमने एकता की सही नीति अपनाई और उसे रेलवे की स्थितियों पर लगा दिया। यह इसलिए संभव हो सका कि इस हड़ताल से पहिले और उसके दौरान हमारे साथियों ने अनेक जगहों पर दमन और आतंक का आघात सहन करते हुए, निस्वार्थ भावना और बहादुरी के साथ कार्य किया।उनमें से अनेक साथी जेलों में डाल दिये गए उन्हें मारापीटा गया। उनके परिवारों को डराया धमकाया गया एवं उन पर तरह-तरह के अत्याचार किए गए। उन्हें छुपकर काम करना पड़ा। किंतु फिर भी उन्होंने अपनी परिस्थितियों में ढील नहीं आने दी और इसीलिए वे अंततः सच्चे स्थानीय नेता के रूप में उभरकर सामने आए।

इस संयुक्त मोर्चे को व्यवहार में बदलने के लिये रेलवे में काम करने वाले हमारे साथियों ने अपनी रेलवे ट्रेड यूनियनों में सही कार्यनीति अपनाई और समय समय पर हड़तालों का सही जायजा लिया उन्होंने सुधारवादी नेतृत्व के प्रभाव क्षेत्र की भी परख की और संयुक्त संघर्षों का भीतरघात करने के उसके कुप्रयासों को विफल बनाया साथ ही बड़ी कुशलता से अन्य संगठनों के बीच ठोस एकता के लिए संघर्ष की नीति को चलाया।

केटेगरी वाइज यूनियनें

हमारे साथियों ने इस रेल हड़ताल से लगभग तीन वर्ष पूर्व ही से रेल मजदूरों की एकता पर बुरा असर डालने वाले कुछ वाकयों को देखा था। उस समय सैक्शन और क्राफ्ट यूनियनों का अचानक ही निर्माण होने लगा था जिनके द्वारा बाद में चलकर एक कन्फ्रेडरेशन बना। हमारे कामरेडों ने उस वक्त यह सही ही महसूस किया कि ये क्राफ्ट यूनियनों का बनाया जाना औद्योगिक यूनियनों के (जो एआईआरएफ का आधार हैं) मुकाबले एक कदम पीछे की ओर जाना होगा, किंतु बावजूद इस सबके, उस प्रकार की कार्रवाइयों

का न तो बाईकाट किया गया और न विरोध ही किया गया क्योंकि ये क्राफ्ट यूनियनें ए.आई.आर.एफ. और एन.एफ.आई.आर. के सुधारवादी नेताओं की निष्क्रियता और असफलताओं के जुर्म के विरुद्ध अस्तित्व में आई थीं। किंतु इसके समांतर, क्राफ्ट और सैक्शन की भावना रेलवे मजदूरों की एकता के लिये, कुछ हलकों में घातक भी समझी जा रही थी। हमारे साथियों ने इसीलिए नई यूनियनों में काम करने का सही निर्णय लिया जिससे कि कालांतर में संयुक्त कार्रवाइयों और संघर्षों के दौरान इन विभिन्न सैक्शनों में एकता कायम की जा सके। इन कैटगरी वाइज यूनियनों के जन्म ने शीघ्र ही संघर्षों एवं आन्दोलनों को जन्म दिया और हमारे साथियों ने इन संघर्षों में पूरी हिस्सेदारी की। ये आंदोलन मान्यताप्राप्त सुधारवादी नेताओं की चोटी ही डुबोने लगे और इस प्रकार नेताओं की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों को मजदूर वर्ग की ओर से चुनौती मिलने लगी।

उभरते हुए संघर्ष

रेलवे फ़ेडरेशन से संबद्ध यूनियनों के अंदर भी स्थानीय आंदोलन होने लगे और हमारे साथियों ने उनका समर्थन किया। उनका नेतृत्व किया जिसके लिये उन्हें सुधारवादी नेताओं द्वारा निकाल बाहर कर दिया गया या फिर कहीं खहीं तो जुझारू ब्रांचों तक को सस्पैंड कर दिया गया।

इन अलग-अलग हुए संघर्षों में काम करते हुए हमारे साथी विभिन्न संगठनों के अंदर संपूर्ण रेल मजदूरों की एकजुटता कायम करने और सैक्शनल भावनाओं को दूर करने के लिए प्रचार करते रहे।

१९७१-७२ तक आते आते आम असंतोष सिर्फ अलग से संगठन बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। यह असंतोष बार-बार स्थानीय आंदोलनों के रूप में ए. आई. आर. एफ. के सुधारवादी नेतृत्व की चुटिया भी डुबोने लगा। दक्षिण भारत में १९७० में लोको कर्मचारियों का संघर्ष इस दिशा में सबसे पहला लक्षण था। एक ओर जहां हम कोशिश कर रहे थे कि सभी सैक्शन इकट्ठे हड़ताल करें, वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण सैक्शनों के सुधारवादी नेताओं के उदासीन, विरोध पूर्ण और फूटवादी रवैये के सामने सब्र कर पाना मुश्किल था। इस प्रकार यह भी खतरा था कि मजदूरों की शक्ति एवं गुस्सा कहीं सैक्शनों की लड़ाइयों में ही न बिखर जाय। किंतु हमारे साथी इस आक्रोश को एक संयुक्त संघर्ष में तब्दील करने की भरसक कोशिश करते रहे।

एल० आर० एस० ए० की हड़ताल

सी.आई.टी.यू. की एर्नाकुलम कान्फ्रेंस (१९७३) में, लोको स्टाफ से संबंधित सवाल ज्यादा उभर कर सामने आया और 'काम के घंटे' के प्रमुख सवाल पर खुले संघर्ष के विस्फोट की संभावना दिखाई देने लगी। ठीक यही वह समय था जब वेतन आयोग की नई सिफारिशें आयी थीं और सभी रेलवे कर्मचारियों और केन्द्रीय कर्मचारियों को आंदोलित करने की संभावनाएं पैदा हो गई थीं।

फिर भी ए.आई.आर.एफ. के नेताओं ने भीतरघात की नीति जारी रखी। एल.आर.एस.ए. के समर्थकों ने फौरन ही संघर्ष की माँग की। अगस्त तक आते-आते एल.आर.एस.ए. की हड़ताल एक तथ्य बन गई और अंततः विजयी हुई। सरकार को समझौते के लिए आना पड़ा और काम के घण्टों को घटाकर काम के १० घंटों की घोषणा करनी पड़ी। आजादी के बाद रेल कर्मचारियों की यह एक सबसे बड़ी सफलता और जीत थी। इसका सबसे बड़ा महत्व तो यह था कि ए.आई.आर.एफ. के उन नेताओं के सिर पर से गुजर कर (जो स्वयं समझौतापरस्ती और फूटवाद के पुराने हथकण्डों को अपना रहे थे और जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा पिछले तीन दशकों में पाला-पोसा गया था) इस संघर्ष ने सारी रियायतें हासिल की थीं।

एल.आर.एस.ए. के जुझारू कार्यकर्त्ताओं ने इन तीन हड़तालों में प्रमुख भूमिका निभाई और इसे बहुत सी गलतियां करने से बचाया जो केटेगरी वाइज और सैक्शनवादी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप पैदा हुई थीं। इस प्रक्रिया में उनकी स्थिति और सुधरी और अंततः उन्होंने अखिल भारतीय रेल हड़ताल के दौरान भी प्रमुख भूमिका निभाई।

मई से पूर्व ही रेलवे के इतिहास में बहुत सी हड़तालें दर्ज हुई हैं।

ए.आई.आर.एफ. में बदलाव

ए.आई.आर.एफ. के पहिले से चले आते नेतृत्व ने इन आंदोलनों पर कीचड़ उछाली और उनको दबाने में अधिकारियों की मदद की किन्तु समय बहुत तेजी से बदल रहा था। सितंबर १९७३ में ए.आई.

आर.एफ. की सालाना मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के असंतोष ने अभिव्यक्ति पाई। वहाँ हड़ताल के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया और जनरल सैक्रेट्री की रिपोर्ट में, हमारे समर्थन से एक संशोधन भी पारित किया गया जो सभी रेलवे संगठनों के माध्यम से ए.आई. आर.एफ. से रेल कर्मचारियों के प्रतिरोध को एकजुट करने की पहल-कदमी की मांग करता था। यह बात पुराने नेतृत्व के लिए एक अभिशाप की तरह थी और रेलवे बोर्ड के साथ उनके सहयोग के खिलाफ जाती थी। जार्ज फर्नांडीज नए प्रैसीडेन्ट के रूप में चुने गए। हालाँकि और दूसरे पदाधिकारी पुराने ही रहे, फर्नांडीज के चुनाव ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसने रेलवे आंदोलन को और भी प्रेरित किया।

संघर्ष के केन्द्रीय और सुसंयोजित विकास के लिए ए.आई.आर. एफ. के अंदर हुई ये घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। सुधारवादी नेतृत्व को साख निरन्तर कम होते जाने के बावजूद और रेलवे कर्मचारियों के अनेक हिस्सों के अलग चले जाने के बावजूद ए.आई.आर.एफ. और उससे संबद्ध यूनियनें अभी भी प्रर्याप्त प्रभावशाली थीं और उनकी हिस्सेदारी के बिना कोई भी अखिल भारतीय पैमाने का संघर्ष संभव नहीं था। दूसरे, दूसरे संगठन सिर्फ सैक्शनल संघर्ष चलाने की क्षमता तो रखते थे किन्तु वे एकजुट तब तक नहीं हो सकते थे जब तक ए.आई.आर.एफ. अपने नीचे के आम कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं बनाता और इस प्रकार एकता और संघर्ष के लिए अपने नेताओं को मजबूर नहीं करता।

सिर्फ इस बिनाह पर कि सुधारवादी नेतृत्व के बावजूद बहुत से संघर्ष हुए, हमने ए.आई.आर.एफ के प्रभाव को कम करके नहीं आंका। हमारी राय थी कि फर्नांडीज के चुनाव ने रेलकर्मचारियों में नई आशाओं का संचार किया, कि जार्ज फर्नांडीज आंदोलन की ओर कदम उठाएंगे, साथ ही हमने एकता के लिए संघर्ष के संदर्भ में अन्य संगठनों की भूमिका की भी उपेक्षा नहीं की।

दूसरे संगठनों में एकता के लिए संघर्ष

दूसरे संगठनों के अन्तर्गत हमें एकता स्थापित करने के लिए संघर्ष की दिशा में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी। एल. आर.एस.ए. और कैटैगरी वाइज़ यूनियनों की फैडरेशन में संगठित

मजदूरों की ए.आई.आर.एफ. के नेताओं के बारे में अलग-अलग धारणाएं और आपत्तियाँ थीं ! उनके बहुत से नेता ए.आई.आर.एफ. के पुराने अनुभवों को भूले नहीं थे और कुछ बेहद संकीर्णतावादी दृष्टिकोण के शिकार थे और उनसे अलग ही रहना चाहते थे।

हमारे साथियों को अपने संगठन के भीतर संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की ए.आई.आर.एफ. विरोधी और लगातार फूटवादी लाइन के कारण और भी जटिल बना दिया गया। दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के रेलवे के संगठनों ने हड़ताल एवं ए.आई.आर.एफ. के साथ सहयोग के विरुद्ध फूटवादी रवैया अपनाया। यही नहीं, सितम्बर में हुए फैडरेशन के सत्र में उन्होंने फर्नान्डीज़ को हराने और पीटर अल्वारेस को जिताने में कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी। वे अपने आप एक नई फैडरेशन शुरू करने की तैयारी कर चुके थे जिसके लिए उन्हें सरकार से मान्यता प्राप्ति की आशा भी थी। इसलिए फर्नांडीज़ के चुनाव के बाद किसी भी प्रकार के संयुक्त मोर्चे के विकास से दूसरों को बाहर रखते हुए वे फैडरेशन को नेस्तनाबूद करने पर अमादा थे।

एल.आर.एस.ए. में भी परेशानियां सामने आईं। इसके द्वारा प्रेरित हड़तालों की सफलता और उनके प्रति ए.आई.आर.एफ. के नेतृत्व के रखने पुनः केटेगरी वाइज़ भावनाओं को, और मनमुटाव को और भी मजबूत किया। कुछने तो यहां तक सोच डाला कि इन्हें रेल मजदूरों की सहायता के बिना ही वे अपने आप संघर्ष को जीत सकते हैं। दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट और दूसरे तत्व जो एकता की पीठ में छुरा घोंपना चाहते थे, इन भावनाओं का इस्तैमाल कर रहे थे जिससे कि एल.आर.एस.ए., ए.आई.आर.एफ. द्वारा बुलाये जा रहे कन्वेंशन से बाहर ही रहा आए। कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी इस जाल में आ भी गए और वे ए.आई.आर.एफ. के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग की बुरी तरह से खिलाफत कर रहे थे। फिर भी, सही लाइन अपनाने वाले बहुत से नेताओं द्वारा की गई एकता की अपील और फरवरी कन्वेन्शन में शामिल होने का प्रस्ताव आखिरकार पास हो ही गया और इस प्रकार बहुमत ने इस लाइन को एक सही कदम के रूप में स्वीकार किया।

इसी तरह से, कन्फेडेरेशन के नेता लोग भी ए.आई.आर.एफ. के साथ हाथ मिलाने के विरोध में थे। कन्फेडेरेशन ने फरवरी

१९७४ में मद्रास में स्वयं ही एक मीटिंग बुलाई जिसमें सी.आई.टी.यू. सहित अन्य ट्रेड यूनियनों को भी आमंत्रित किया।

शुरूआत में, इस बड़ी और प्रतिनिधित्व वाली बैठक में, ए.आई.आर.एफ. के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने के प्रति तीखा विरोध था। दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने इसे यहां घोषित भी किया और खुले तौर पर कहा कि कन्फेडेरेशन की फरवरी कन्वेशन में भाग नहीं लेना चाहिए। शायद इस प्रकार की आम राय हावी भी हो गई होती (चाहे वह आम मजदूरों के वास्तविक रुख को अभिव्यक्त न कर पाती) और यदि ऐसा हुआ होता तो इतने मजदूरों के लक्ष्य को भारी हानि पहुंचाई होती।

किन्तु कामरेड उमानाथ की एकता की सशक्त अपील के बाद लोगों में एकता के पक्ष में अनुकूल भावना पैदा हुई और फलस्वरूप एक के बाद एक संगठनों ने संयुक्त कार्रवाई की माँग की। एटक के प्रतिनिधि ने भी अंततः एकता के लिए अपनी आवाज बुलंद की और इस तरह फरवरी कन्वेंशन के लिए जमीन तैयार हुई।

सैकड़ों संगठन एकजुट हुए

ए.आइ.आर.एफ. के तत्वाधान में आयोजित कन्वेंशन इन्टक की एन.एफ.आई.आर. को छोड़कर लएभग १०० संगठनों के ३,५०० से भी अधिक डैलीगेटों के कारण एक बड़े प्रदर्शन में रूपांतरित हो गया। अन्य संगठनों के साथ ही साथ सी.आई.टी.यू. भी कन्वेंशन में निमंत्रित की गई।

यह कन्वेंशन कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इसने रेल मजदूरों में व्याप्त एकजुट-संघर्ष की मांग को ठोस रूप दिया। यह पहला मौका था जब ए.आई.आर.एफ. के नेता अन्य संगठनों से हाथ मिला रहे थे और रेलवे बोर्ड के साथ अपने गठबंधन को तोड़ रहे थे। एन.सी.सी.आर. एस—जिसके निर्माण में कामरेड समर मुखर्जी ने एक प्रमुख भूमिका अदा की—अब यह सिर्फ संयुक्त नेतृत्व का संगठन मात्र नहीं थी अपितु इसने सुधारवादी नेतृत्व के अधिकारियों के साथ समझौतापरस्ती के मृतप्राय बोझ को कम कर दिया था और ए.आई.आर.एफ. एवं अन्य संगठनों के संयुक्त नेतृत्व के हाथ में सारी पहलकदमी सौंप दी थी।

इस प्रकार, एकता के साथ-साथ हमारे द्वारा भीतरघात करने वालों के विरुद्ध भी संघर्ष जारी किया गया। रेल हड़ताल की कहानी इंदिरा सरकार की दानवी निष्ठुरता की एक लम्बी गाथा है।

रेल हड़ताल के दौरान

हड़ताल के दौरान हमने मजदूरों के संघर्ष और एकता के अपने संघर्ष को कैसे जारी रखा? हड़ताल का संचालन वास्तव में एन.सी.सी.आर.एस. के विभिन्न घटकों की चेतना और समझदारी के अंतर्संबंधों के द्वारा ही तै होता था। एन.सी.सी.आर.एस. के अंदर हमारे साथी लोग किसी निर्णायक स्थिति में नहीं थे। इसके अलावा उनमें कुछ गिरफ्तार भी हो चुके थे।

यह शुरू से जाहिर हो गया था कि आंन्दोलन के कुछेक हिस्सेदारों को इस संघर्ष की व्याप्ति एवं ताकत और उस भयंकर दमन का अंदाजा नहीं था जो बाद में जारी होना था और जिसे कर्मचारियों के द्वारा धैर्य से बर्दाश्त करना था।

वास्तव में मजदूरों का प्रतिरोध हमारे पूर्वानुमानों से ज्यादह ही निकला।

विभिन्न रेलवे यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की मुख्य समिति ने इस हड़ताल को भी सामान्य ट्रेड यूनियन मात्र के रूप में ही समझा। उनका अनुमान यह था कि यह हड़ताल ज्यादह से ज्यादह सात दिन तक चल पायेगी जिसके दौरान कोई न कोई समझौता हो ही जाएगा। इस तरह उन्होंने किसी नैतिक विजय की कल्पना कर रखी थी जो उन्हें संगठन को मजबूत करने में शायद मदद करती!!

इसीलिए ऐन हड़ताल के दिन समझौता वार्ता शुरू कर दी गई और धोखे भरे समझौता-सूत्र प्रसारित किये जाने लगे।

हड़ताल के पहले सप्ताह में आंदोलन के आधार को और भी मजबूत बनाने, संभावित दानवी दमन के खिलाफ आंदोलनकारी मजदूरों को गोलबन्द करने और उनके अत्याचारों के खिलाफ़ जनता को जागृत करने के लिए ठोस कदम उठाने की सबसे ज्यादह जरूरत थी। इसलिये नेतृत्व के स्तर पर चलने वाली इन समझौता वार्ताओं ने आम मजदूरों के ध्यान को इस प्रमुख काम से हटा दिया।

हम इस प्रकार की प्रक्रिया को रोकने की हालत में नहीं थे। हम सिर्फ इस प्रक्रिया से पैदा होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश भर कर सकते थे।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, छः केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा १५ मई को रेल हड़ताल के समर्थन में अखिल भारतीय एकता दिवस मनाने के आह्वान में भारी सफलता प्राप्त की थी। इसके बावजूद १६ मई को हुई केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की बैठक में **एटक** के श्री पाद अमृत डाँगे ने प्रस्ताव रखा कि हड़ताल वापस ली जानी चाहिए। उनकी यह कोशिश सी.आई.टी.यू. के प्रतिनिधि की हैसियत से स्वयं मेरे द्वारा नाकाम की गई थी।

इस प्रकार से साथियो, जैसे-जैसे हड़ताल खिंचती गई, वैसे-वैसे इस प्रकार के प्रस्ताव प्रसारित किये जाने लगे। ऐसी स्थिति में एन.सी.सी.आर.एस. में हमारे साथी कामरेड समर मुखर्जी को उन फूटवादी और समर्पणवादी नीतियों से टक्कर लेने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, जिन्हें **एटक** के नेताओं द्वारा लगातार पेश किया जाता रहा। यह हमारे प्रयत्नों का ही परिणाम था कि मजदूरों को **एटक** के दबाव में आकर नीचा नहीं देखना पड़ा। किन्तु फिर भी अन्य नेताओं के अंदर इस प्रक्रिया में ढुलमुल यकीनी बढ़ी और आखिरी मौके पर, जबकि हालांकि हमारे प्रतिनिधि और ए.आई.आर.एफ. के महामंत्री संघर्ष ज़ारी रखने के पक्ष में थे, फिर भी बहुमत ने दूसरा ही रास्ता चुना।

एटक के नेताओं की गद्दारी

हालाँकि घटकों के अन्य प्रतिनिधियों ने ढुलमुल यकीनी दिखाई और कुछ आरम्भ से मात्र समझौता-वार्ताओं में उलझे रहे, फिर भी उस हड़ताल पर सबसे बड़ा आघात **एटक** का नेतृत्व करने वाले दक्षिण-पंथी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की ओर से ही आया। यह स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि उनकी यूनियनों के नीचे की कतारों ने पूरी वफादारी के साथ संघर्ष चलाया। जबकि इसके ठीक विपरीत उनके उच्च नेताओं ने सरकार के पंचमांगी के रूप में काम किया। प्रत्यक्ष रूप में वे मज़दूरों के रुख के साथ-साथ चलते रहे, किंतु अंदर से उन्हें कमजोर करते रहे और अंत में संघर्ष की कठिन घड़ी में खले आम हड़ताल तोड़क के रूप में सामने आ गये।

दूसरी अन्य हड़तालों के दौरान भी उन्होंने ऐसी ही भूमिकाएं अदा की हैं। १९७३ में बम्बई में कपड़ा मिलों की हड़ताल—जिसने ढाई लाख मजदूरों को गोलबंद किया हुआ था, के दौरान भी डांगे साहब ने एक तरफ भारी लफ़्फाजी से भरा हुआ भाषण दिया और दूसरी ओर अचानक ही मिल मालिकों से समझौता कर डाला और इस तरह ३२ दिन पुरानी हड़ताल का भीतरघात किया। इंटक के नेता लोग भी प्रायः ऐसा ही किया करते हैं। मजदूरों के आन्दोलनकारी दबाव को रोक पाने में असमर्थ ये लोए आन्दोलनों का सिर्फ इस लिए समर्थन करते दिखाई देते हैं कि संघर्ष की कठिन घड़ी में वे उसकी पीठ में छुरा घोंप सकें। ठीक ऐसी ही बात फरवरी में हुई हड़ताल के दौरान गोदी-मजदूरों के नेताओं ने की थी। रेल हड़ताल के दौरान इस प्रकार की हड़ताल-तोड़क नीति और भी बेशरमी के साथ सामने आई।

दक्षिण पंथी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग दूसरे नेताओं की पीठ के पीछे सरकार के साथ गुप्त सौदेबाजी में लगे हुए थे।

जब सरकार ने एन.सी.सी.आर.एस. के गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने से मना कर दिया तो डाँगे साहब ने सुझाव दिया कि जो लोग जेलों से बाहर हैं,उन्हें समझौता वार्ता जारी रखनी चाहिए। यह सुझाव एन.सी.सी.आर.एस. के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इस समय भी, डाँगे साहब एक और फार्मूले को ईजाद करके ले आये जिसमें हड़ताल कि मुख्य मांगे गायब थीं। डाँगे साहब ने सुझाव दिया कि बोनस, वेतनमान में संशोधन इत्यादि मांगों को एक समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए और इस तरह समझौता-वार्ता आरम्भ कर दी जानी चाहिए।

हड़ताल पर संपूर्ण समर्पण के लिए बढ़ाए जा रहे सरकार के दबाव और एन.सी.सी.आर.एस. के अन्दर इस प्रकार के समझौता प्रस्तावों पर असहमति देखकर डांगे साहब ने अचानक यह प्रस्ताव रखा कि यदि हड़ताल बिना शर्त वापस ले ली जाती है तो वह सरकार से रेल कर्मचारियों का अपघात (विक्टिमाइजेशन) न करने का आश्वासन ले सकते हैं।

इस सिलसिले में लोगों ने जब उनसे यह पूछना आरम्भ कर दिया कि क्या वे किसी गुप्त सौदेबाजी में मशगूल हैं तो उन्होंने अपना यह प्रस्ताव वापस ले लिया। यही नहीं, वे एसे ऐसे बयान

जारी करने लगे जिनमें सरकार के खिलाफ भयंकर हमले भरी लफ्फाजी भरी होती थी। उन्होंने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर दमन विरोधी दिवस का भी आह्वान किया। किन्तु ठीक अगले दिन, किसी भी पार्टी या एन.सी.सी.आर.एस. या केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सलाह मशविरा किए बिना ही उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि हड़ताल वापस लेने से संबंधित कोई भी फैसला अलग क्षेत्रों और ग्रुपों में अलग अलग ही लिया जाना चाहिए। यह एकता में फूट डालने और क्षेत्रों के स्तर पर (जोनल स्तर पर) हड़ताल तोड़ने का खुला प्रस्ताव था। इतने पर भी उन्हें यह करने में कोई शर्म नहीं आई कि उनका संगठन एन.सी.सी. आर.एस.के निर्णयों को ही लागू करेगा।

समझौता प्रस्तावों की नीति से हमारी नीति के फर्क को का० समर मुखर्जी और प्रिय गुप्त द्वारा अपने आखिरी बयानों में इस तरह कहा गया कि वे दोनों हड़ताल की एकतरफा वापिसी के विरुद्ध हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

आम मजदूरों की राय लिए बिना हड़ताल की एकतरफा वापिसी की नीति निश्चय ही एक गलती थी। वास्तव में, यह कदम कतई अजनतांत्रिक था।

मजदूरों की नीचे की कतारों के अन्दर हड़ताल के संदर्भ में किसी भी प्रकार की पहलकदमी की भावना अभाव के कारण ऐसा होना अनिवार्य था।

हमारी कमियां

रेलवे के स्तर पर हमारे काम की कमियां इस बात से प्रकट होती हैं कि हम एन.सी.सी.आर.एस. समितियों के निचले स्तरों पर एक व्यापक जाल बिछाने में असमर्थ रहे। एन.सी.सी.आर.एस. के निर्माण और हड़ताल ने एकजुटता की ऐसी अभूतपूर्व भावना का विकास किया कि संगठनात्मक स्तर पर आने वाले अवरोध, पार्टी-पार्टी के बीच के अवरोध—सभी ध्वस्त हो गए। जरा सी पहल-कदमी और संगठनात्मक शक्ति के समुचित उपयोग के माध्यम से पर्याप्त उभार बरकरार रखा जा सकता था। इस तरह कहा जा सकता है कि एकता को विकसित करने के अनुकूल पैदा हुई स्थितियों का पूरा उपयोग करने की दिशा में हम संगठनात्मक रूप

से नाकामयाब रहे। यदि हम कामयाब रहे होते तो निचले स्तर पर नेतृत्व की एक ठोस आधार-शिला तैयार हो गई होती।

नीचे आधार क्षेत्र में हमारी कमियों ने बहुत सी स्थानीय संयोजन समितियों, यूनियनों एवं संगठनों के आन्दोलनों के संदर्भ में अन्दरूनी निर्णयकारी संगठन प्रक्रिया को असंभव बना दिया। समूचे आन्दोलन के दौरान आन्दोलन के नेतृत्व का ध्रुवबिन्दु, वहीं का वहीं रहा। वह जार्ज फर्नांडीज और एन.सी.सी.आर. एस. के ऊपरी नेताओं के गिर्द ही बना रहा। नेतृत्व के साथ नीचे की कतारों से निकल सकने वाले नए नेतृत्व में कोई समुचित सह-संबंध नहीं पैदा हो सका। इसीलिए हड़ताल की वापसी को सभी मजदूरों ने आसानी से स्वीकार कर लिया। हालांकि यह भी सच है कि हड़ताल क्रमशः कमजोर पड़ती जा रही थी। यही कारण है कि जार्ज फर्नांडीज, बावजूद सारी बातों के, रेल मजदूरों में न केवल अपनी प्रतिष्ठा कायम रख सके अपितु वह कुछ बढ़ी ही है। बंबई और अन्य स्थानों पर उनके द्वारा संबोधित बड़ी रैलियां यही बताती हैं कि मजदूर उन्हें हड़ताल-वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के प्रति एक सही लाइन विकसित करने की नज़र से यह बात काफी महत्वपूर्ण है।

हड़ताल की वापसी के बाद भी हमने एकता के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा। हमारे प्रतिनिधियों ने एन.सी.सी.आर.एस. औरउसके कन्वेंशन के पुर्न आयोजन के लिए बराबर आग्रह किया है। हमारे साथी प्रत्येक संगठन में बढ़ रही निराशावादी प्रवृतियों और मजदूरों से अपघात (विक्टिमाइजेशन) के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आज हमें ही एकता का नारा बुलंद करना पड़ रहा है।

१९७४ की बंबई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल

साथियो, १९७४ में बंबई की कपड़ा मजदूरों की हड़ताल, जो ४२ दिन तक चली, हमारे संयुक्त संघर्ष और संशोधनवादी डाँगे साहब के नेतृत्व की फूटवादी कार्यनीति के बरखिलाफ़ सतत् संघर्ष के प्रयासों का एक और उदाहरण है।

बंबई में, कपड़ा मजदूरों का प्रमुख हिस्सा राष्ट्रीय एम.एम. यूनियन के प्रभाव में है। एटक से संबद्ध अपने पुराने प्रभाव की विरासत पर टिकी हुई गिरनी कामगार यूनियन भी वहां एक शक्ति

के रूप में स्थित है। हमारी यूनियन भी दिन प्रतिदिन अपने अस्तित्व का अहसास कराती जा रही है और अपनी पहलकदमी और अभियान क्षमता के द्वारा गिरनी कामगार यूनियन को भी संयुक्त कार्रवाइयों में खींचने में प्रायः समर्थ रहती है। इसके अलावा **लाल निशान** का कपड़ा कामगार संगठन भी वहाँ है।

१९७४ के मध्य में, मुद्रास्फीति के बढ़ाव और कपड़ा मजदूरों को दूसरे मजदूरों के मुकाबले तनुखाह कम होने के कारण वेतनमानों में तत्कालवृद्धि डी.ए. में वृद्धि एवं आकश्यकता पर आधारित वेतन के सवाल फौरी तौर पर सामने उठ खड़े हुए। हमारी यूनियन और लाल निशान ने मिलकर गिरनी कामगार यूनियन समेत अन्य संगठनों को भी हड़ताल की तारीख तय करने को बुलाया।

यह देखते हुए कि ऊपर के मसलों के ऊपर मजदूरों में हवा गर्म होती जा रही है, संशोधनवादियों ने बैठक में भाग लिया और ३० सितंबर के लिए एक हड़ताल का नोटिस जारी करने के प्रति वे सहमत हो गए। शायद उन्हें अभी भी संदेह था, इसलिए उन्होंने सुझाया कि हड़ताल का यह नोटिस, लिखित में देने की बजाए एक दिन की हड़ताल (हड़ताल की घोषित तिथि से १४ दिन पहले ही) के माध्यम से दिया जाना चाहिए। उनके दुर्भाग्यवश, १६ दिसम्बर की यह हड़ताल शत प्रतिशत सफल रही। उनका अन्दाजा शायद यह था कि एक दिन की भारी और सफल हड़ताल से डरकर मालिक लोग और सरकार उन्हें कुछ रियायतें प्रदान कर देंगे।

किन्तु, जब ऐसा नहीं हुआ और हड़ताल आरम्भ हुई तो संगठनात्मक स्तर पर आन्दोलन का भीतरघात आरम्भ हुआ। १६ तारीख में एकता के इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद गिरनी कामगार यूनियन के नेताओं ने तीनों संगठनों की एक संयुक्त हड़ताल समिति बनाने का विरोध किया।

मजदूरों ने इंटक द्वारा किए गए सौदे को ठुकरा दिया और हड़-२९-३० से आरम्भ हो ही गई। दो लाख मजदूरों के पूरी तरह हड़ताल पर चले जाने के बावजूद संशोधनवादी नेताओं ने हड़ताल के संचालन के लिए संयुक्त हड़ताल समिति बनाने से इन्कार कर दिया। शायद ऐसा कदम उनके गुप्त समझौते और योजनाओं के आड़े आता होगा!

सच तो यह कि डाँगे साहब तो ६ जनवरी को ही समझौता करने की जल्दबाजी में थे और उन्होंने एक बेहद घटिया समझौता प्रस्तावित भी किया था जिसे हमने ठुकरा दिया।

यह हड़ताल हफ्तों चली किन्तु यहां एक प्रकार की अजीब एकता दिखाई दी। हर रोज़ अलग अलग मंचों से दो मीटिंगें होती थीं। (सी.आई.टी.यू. और लाल निशान मिलकर इकट्ठी मीटिंगें किया करते थे)। इस आन्दोलन में न केवल किसी संयुक्त-समिति का अभाव स्पष्ट था अपितु यहां संयुक्त मीटिंगों तक का अभाव भी रहा। संयुक्त कार्रवाई के नाम, चालू मिलों के सामने एक संयुक्त प्रदर्शन ही हो सका। १६ जनवरी को महाराष्ट्र सचिवालय के सामने एक और संयुक्त प्रदर्शन हुआ था। जब संयुक्त प्रतिनिधियों ने मुख्य मंत्री से भेंट की और जब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा तब आम मजदूरों ने एक स्वर से माँग की कि अलग-अलग मीटिंगें बंद की जाएं, और सिर्फ संयुक्त मीटिंगें की जाएँ। इस तरह हड़ताल की शुरूआत के लगभग तीन सप्ताह बाद १८ जनवरी को पहली मीटिंग संभव हो सकी।

अगले तीन सप्ताह और बीते। हड़ताल फिर भी कमजोर नहीं पड़ी। डांगे साहब ने फिर ७ फरवरी वाले प्रस्तावों को पुर्न जीवित किया और उनको हमारे द्वारा एक बार फिर से ठुकरा दिया गया। किन्तु ८ फरवरी को ही डांगे साहब और गिरनी कामगार यूनियन के नेताओं ने हमारे द्वारा ठुकराए गए उक्त प्रस्तावों और शर्तों को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार ९ फरवरी को हड़ताल को वापस ले लिया गया। इस प्रकार एकता के टूट जाने के कारण मजदूर निराश हुए और संघर्ष से पीछे हट गए।

'संघर्ष का नेतृत्व इसलिए किया जाए ताकि उसकी पीठ में छुरा घोंपा जा सके।' —वाली मिसाल यहां फिर चरितार्थ हुई। यह बात सिद्ध करती है कि दक्षिणपंथी कम्युनिस्टों और **एटक** के नेतृत्व की नीति संघर्षों को भीतर से तोड़ने की है। सवाल यह उठता है कि वे ऐसा करने के बावजूद बच के कैसे निकल जाते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं वे अपना प्रभाव तेजी से खोते चले जा रहे हैं। यह एक ऐसा तत्व है जो हम अखिल भारतीय स्तर पर घटता हुआ देख सकते हैं। किन्तु बंबई की इस हड़ताल के संदर्भ में हम यह नहीं कह सकते कि इस हड़ताल के बाद उनका असर इतना घटा है

कि अब वे कपड़ा मजदूरों की एकता के संघर्ष की प्रक्रिया में एक उपेक्षणीय तत्व बन कर ही रह गए हैं। दरअसल सुधारवाद से मजदूरों के मुक्त होने की प्रक्रिया में पुरानी चली आती हुई वफ़ादारी और श्रद्धा आड़े आ जाती है। हम लोग और हमारे जैसे अन्य जुझारू कार्यकर्त्ता जिसे गद्दारी कहते हैं, जनता के बड़े हिस्से द्वारा अभी भी उसे सिर्फ 'भूल' या 'निर्णय की गलती' मानलिया जाता है। कभी कभी तो मजदूरों के पिछड़े हुए हिस्सों द्वारा इस गद्दारी को एक सही निर्णय के रूप तक में मान लिया जाता है। यही कारण है कि बंबई में हमें फिर से **एटक** के साथ संयुक्त मोर्चे की कोशिश करनी पड़ेगी।

मजदूरों को शिक्षित करने में हमारी असफलता के कारण व्यापक आधार वाली हड़ताल समितियों के विकास में हमारी नाकामयाबी मजदूर वर्ग की एक खास स्तर की चेतना की कमी को उद्घाटित करती है। इस चेतना के अभाव के कारण, इस प्रकार की एकता सिर्फ ऊपरी एकता, या सिर्फ कुछेक नेताओं की एकता के रूप में हमारे सामने आकर के रह जाती है।

संयुक्त हड़ताल समितियों के अपने प्रस्तावों को हम किस हद तक जनता के बीच ले जा सकें, एक संघर्ष के दौरान संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदारों की आलोचना से संबंधित सवालों को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। चेतना के अभाव में इस तरह के कदमों को गलत भी समझा जा सकता है। किन्तु क्या हमने बाक़ई ऐसे सवालात या मसले उठाए ? ऐसे मसलों को उठाने के बाद, यदि उनके महत्व को जनता के द्वारा नहीं समझा जाता तो इसका मतलब होता है कि लोगों में हड़ताल की कार्यविधि के बारे में आवश्यक चेतना का निश्चय ही अभाव है। इसी कमी के कारण ही, सुधार-वादी नेतृत्व यूनियनों और आन्दोलनों के आवश्यक जनतांत्रिक संचालन पर हावी होकर मनमानी सवारी गांठ लेता है।

एक और सवाल : क्या हमने स्वयं भी लाल निशान वालों के साथ मिलकर, उनसे हर स्तर पर सलाह मशविरा करने, हर स्तर पर नए नेतृत्व का विकास मार्ग खोलते हुए, व्यापक आधार वाली संयुक्त हड़ताल समितियाँ बनाईं ? यदि इतना भी किया गया होता तो १६ जनवरी की बैठक में संयुक्त-मीटिंगों की मांग के बाद, इन समितियों को सक्रिय किया जा सका होता। कहना न होगा कि

किसी को यह भी स्पष्ट नहीं कि १६ जनवरी से १ फरवरी के बीच संयुक्त मीटिंगों और संयुक्त समितियों के लिए क्या क्या किया गया ?

दुर्गापुर हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाईज यूनियन

कामरेड,

हम सब को दुर्गापुर यूनियन के नेताओं को बधाई देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मजदूरों की एकता कायम करने वाले तत्वों के खिलाफ लड़ने का महान काम ऐसे समय में किया है जब कि वहाँ गुन्डों की मदद से मज़दूरों पर अर्द्धफासिस्टी आतंक, हत्याओं और मजदूर साथियों के घरों पर हमलों का बोलबाला था। हालांकि गुण्डों के हमलों के कारण हमारा यूनियन-आफिस अभी भी बन्द है, प्रशासन और काँग्रेस की यूनियन व गुण्डे हर तरह का झूठा प्रचार कर रहे हैं, अवसर-वादी **एटक** के नेता सरकार के इरादों की गुलामी कर रहे हैं, फिर भी हमारे कामरेड मजदूर - एकता की नीति पर चल रहे हैं, इसलिए दुश्मन के सारे दांवपेंच नाकामयाब साबित हुए हैं। वहाँ की खास समस्या यह भी है कि मजदूर साथियों से संपर्क कैसे किया जाए ? **इंटक** के आतंकवादी रवैये के बावजूद अपने मजदूर साथियों से कैसे मिला जाए ?

इस सिलसिले में उकसावे की कार्रवाई बहुत जल्दी शुरू हो गई : इस सचाई के बावजूद कि हमारी यूनियन ही एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन थी, पदाधिकारियों ने इंटक को स्थान देते हुए त्रिपक्षीय प्लान्ट स्तर की कमेटी का गठन किया। उनका इरादा वास्तव में **इन्टक** को पहलकदमी करने का मौका देना था। उन्होंने यह भी सोचा था कि हम एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन की हैसियत से हम अपने अधिकार हनन के प्रति गुस्सा दिखाएँगे तथा कमेटी का बहिष्कार करेंगे। अधिकारियों के इन इरादों को समझ कर तथा इस समय की राजनैतिक हालत व आतंक को देखते हुए और सारे मजदूर - साथियों जिसमें, इंटक के प्रभाव में आए साथी भी शामिल हैं, के पास पहुँचने की अहमियत को समझते हुए हमारे कामरेडों ने कमेटी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया और उस कमेटी को ही एकता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने वाले हथियार के रूप में बदलने की कोशिश की। हमने जहां मजदूर-वर्ग विरोधी सारे कदमों के खिलाफ लड़ाई की, वहाँ मजदूर-वर्ग के हित में कई ऐसे प्रस्ताव रखे और इंटक, ऐटक आदि से

साथ देने के लिए कहा। साथ ही हमने उस हड़ताल की कार्रवाई का समर्थन किया जिसमें इन्टक के कर्मचारी भी शामिल थे। हमने नेताओं को पीछे लौटना मुश्किल कर दिया। नतीजा यह निकला कि आखिर में इन्टक के नेताओं ने त्रिपक्षीय कमेटी से अपने को अलग कर दिया क्योंकि हमें अलग करने के उनके असली इरादे उससे फलीभूत नहीं हुए। हम चूंकि मीटिंगें करने में असमर्थ थे, यूनियन आफिस में काम नहीं करने दिया जा रहा था, मान्यता समाप्त प्राय करदी गयी थी, ऐसी हालत में यूनियन के कामरेडों ने सीधे प्लान्ट में ही काम करना शुरू कर दिया और जो भी कानूनी तौर पर मौका मिलता था दुर्गापुर में मजदूर-एकता को मजबूत बनाने के लिए उस मौके का भरपूर उपयोग किया और उस कार्य को दूसरे स्टील प्लान्टों में आगे बढ़ाया।

हिन्दुस्तान स्टील एम्लाईज़ यूनियन दुर्गापुर के जो प्रतिनिधि स्टील-वेतन वार्ता कमेटी में काम कर रहे थे उन्होंने कमेटी में जोरदार लड़ाई जारी रखी, वहाँ न केवल मालिक बल्कि इन्टक और ऐटक के प्रतिनिधि भी उनके विरोध में खड़े हो गए। हमारी यूनियन ने विस्तार से मांगों को तैयार किया, पूरे तौर पर तर्क तैयार किए, हमारे द्वारा सुझाई गई दिशा के अनुसार वेतन के सुधार के लिए मजबूत केस बनाया। कमेटी की कार्रवाई को मजदूरों के सामने प्रस्तुत करवाया जिससे अधिकारियों के साथ समझौते करने वालों के लिए मुश्किलें हो गयीं। वेतन के सवाल ने हमें जनता के व्यायक हिस्सों तक अपनी बात पहुँचाने का मौका दिया, इसमें बहुत सा हिस्सा इन्टक का था और इस तरह इस मौके ने एकता के उद्देश्य में मदद दी। हमारे अपने प्रयासों का यह फल हुआ है कि हमारी एकता की अपील भिलाई जमशेदपुर राउरकेला और वास्तव में सभी स्टील उद्योग केन्दों तक पहुँची।

इसी के साथ, दुर्गापुर के कामरेडों की एक और उपलब्धि का ज़िक्र किया जाना चाहिए। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों के किसानों से मिलकर 'किसान सभा' संगठन की शुरूआत भी की और इसमें अच्छी तरह कामयाब हुए। यहीं मैं यह जिक्र कर दूँ कि ठीक इसी तरह की चेतना का परिचय पश्चिमी बंगाल में चाय बागान के कर्मचारियों ने दिया था और कुछ क्षेत्रों में 'किसान सभा' संगठित करने में अगुआई की थी।

एकता के लिए किए गए प्रयासों का ही नतीजा है कि कमेटी में शामिल इन्टक और ऐटक के नेता अब एक आम नजरिये के लिए

बातचीत चला रहे हैं। २६ जुलाई की कन्वेंशन कमेटी जो कि स्टील कर्मचारियों की बढ़ती हुई एकता का फल थी,—ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली है और वह सारे स्टील प्लान्टों के मजदूरों को एकता में बाँधने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार का काम दे रही है।

मानकीकरण कमेटी और **कार्य मूल्यांकन** के विषय में भी हमारे यूनियन-नेताओं ने इसी प्रकार का महत्वपूर्ण काम किया। अधिकारी वर्ग ने जब यह पाया कि अधिकारियों के प्रतिनिधियों के शामिल होते हुए भी कमेटी को मजदूर वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो उन्होंने अपने इरादों का खण्डन करना शुरू कर दिया। इस आतंक के माहौल में भी, दुर्गापुर यूनियन ने एकता का झंडा ऊँचा रखा और प्रतिकूल हालात में भी हड़ताली कार्रवाई की अगुआई की। मजदूरों के हितों के प्रति दृढ़ लगाव को, अलग अलग संस्थाओं के ऐसे चुनावों के नतीजों से देखा जा सकता है जहाँ चुनाव ईमानदारी से हुए। मसलन, जून १९७३ में हुए एलाय स्टील प्लांट की स्पोर्ट्स कमेटी के चुनाव में हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाईज यूनियन को ६० प्रतिशत वोट मिले, इन्टक को ३० प्रतिशत और एटक को १० प्रतिशत। ये नतीजे उन हालातों के हैं जिनमें एलाय स्टील प्लांट के कर्मचारियों पर लगातार आतंक की छाया थी।

कामरेड, आखिर क्या कारण है कि काँग्रेस सरकार के आतंक के बावजूद, इन्टक के नेताओं की हरदफा की गद्दारी के बावजूद कर्मचारियों का एक हिस्सा अभी भी उनके पीछे है? आतंक और भ्रष्टाचार के साथ ही राष्ट्रीय काँग्रेस का जो राजनैतिक प्रभाव मजदूर वर्ग के एक हिस्से पर है, उसे इन्टक के नेता भुनाते हैं। यह एक सचाई है जिसे देखना होगा और यह दिशा तभी बदली जा सकती है जब जल्दी से जल्दी मेहनतकश वर्ग के सामने काँग्रेस की नीतियों का पर्दाफाश हो जाए। इसके अलावा इन्टक छोटी तादाद के कुछ ऐसे लोगों की मदद भी लेती जान पड़ती है जो उत्पादन की महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हैं और प्लांट के कामकाज को ठप्प कर देने में समर्थ हैं।

कामरेड, हड़तालों, विरोधों और मेहनतकश वर्ग के व्यापक आन्दोलनों में आबादी के बड़े हिस्सों पर असर डालने की ताकत होती है। मजदूरवर्ग एकजुट होकर जो वेतन के लिए हड़तालें

करता है उनमें देहाती आवाम को आन्दोलित करने की भी एक भूमिका होती है। जूट मजदूरों की संगठित हड़ताल ने जूट पैदा करने वाले किसानों को उचित दाम देने की मांग को आगे बढ़कर उठाया है। मई १९७३ में बम्बई में यूनाइटेड यूनियन कमेटी ने अकालग्रस्त देहाती जनता को दी जाने वाली सहायता के दौरान किए गए आचरण के विरोध में प्रोटेस्ट कार्रवाई करने का आह्वान किया था। इनके आह्वान पर लाखों खेतिहर मजदूर और गरीब किसान हड़ताल पर रहे थे।

चटकल मजदूरों की हड़ताल

कामरेड, हमारी चटकल यूनियन की अगुआई में हुई जूट मजदूरों की दो बड़ी हड़तालों का अनुभव भी काफी ज्ञानवर्धक है। सी.आई.टी.यू. की शक्ति और ताकत को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि इस अवधि में होने वाली लगभग सभी बड़ी हड़तालों में हमारी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, और कुछेक में हम सब बड़े हिस्सेदार थे।

पश्चिम बंगाल की जिन दो जूट हड़तालों में हरबार दो लाख कर्मचारी शामिल हुए थे, उनका अपना एक महत्व है। ये हड़तालें न केवल अर्द्धफासिस्टी आतंक के दौरदौरे में ही नहीं हुई, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो सीधा आतंक उनके सामने था। पिछले तीन वर्षों के पूरे समय के दौरान जब से आतंक शुरू हुआ है, एवं इन दो हड़तालों के दौरान कई हफ्तों तक बैरकपुर इलाके तथा कुछ अन्य इलाकों में जहां हजारों मजदूर रहते थे, न कोई मीटिंग हो पायी न कोई प्रदर्शन और न खुले तौर पर यूनियन का काम हो सका। और फिर भी दोनों हड़तालें सफल रहीं, उनमें सौ फीसदी मजदूरों ने हिस्सा लिया। १९७४ की हड़ताल ३४ दिन चली, और १९७५ की हड़ताल ४६ दिन तक चलती रही।

मजदूरों और उनकी यूनियन के खिलाफ आतंक और दमन के जो जो हथकंडे अख्तियार किए गए हैं उनकी जड़ें काँग्रेस पार्टी और उसकी सरकार में हैं। फिर भी काँग्रेस पार्टी की यूनियन—इन्टक के साथ हमें सम्मिलित मोर्चा बनाना पड़ता है।

जूट कर्मचारियों के बीच उनकी न मानी गयी माँगों को लेकर तेजी से बढ़ते हुए असन्तोष के बावजूद, इन्टक और काँग्रेसी शासक १९७४ में यह सोचते थे कि इन्टक नेताओं का तोड़ फोड़ का प्रभाव

और बुरी तरह से फैलाया गया आतंक हमें और मजदूरों को इन्टक के द्वारा मान लिए गए समझौते को मानने के लिए मजबूर कर देगा। इन्टक के नेताओं ने खुलकर गद्दारी की थी और आई.जे. एम.ए. तथा काँग्रेसी श्रम मंत्री के कहने से अकेले ही उस समझौते पर दस्तखत कर दिए थे। बातचीत के दौरान इन्टक के नेता लोग अपने सहयोगी एटक से अलग पड़ गए।

उनके (इंटक) के प्रेसीडेन्ट ने समझौते पर दस्तखत करने से इन्कार कर दिया। एटक के नेताओं ने इसका उल्लंघन किया और हड़ताल में शामिल हो गए। इस हड़ताल का संचालन सी आई टी यू ने दोनों यू.टी.यू.सी., एटक और एच.एम.एस. के एक हिस्से के सहयोग से किया।

हड़ताल की शुरूआत हुई तो **इन्टक** आन्दोलन से कट गई और दूसरे ट्रेड यूनियन के संगठनों के साथ पूरी एकता कायम हुई। हमें इस बात का गर्व है कि यह मिलीजुली हड़ताल अखिल भारतीय स्तर पर जूट मजदूरों की पहली हड़ताल थी। आंध्र प्रदेश को छोड़कर यह सभी राज्यों में फैल गयी थी।

यह स्पष्ट है कि अधिकृत क्षेत्रों में आतंक के बाबजूद यदि सी.आई.टी.यू. यूनियन घनघोर काम करने के तरीके और तरकीबें न ढूंढ़ निकालती तो हड़ताल कामयाब नहीं होती। हालांकि, हम लोग एक बड़ी ताकत थे, और बिना हमारे वहां हड़ताल करने का सवाल ही नहीं उठता।

इन्टक के समझौते की पूरी नाकामयाबी और हड़ताल की कामयाबी से आतंक और काँग्रेस की श्रम नीतियों पर एक करारी राजनैतिक हार की चोट पहुँची जिसका श्रेय एकता में बँधे जूट मजदूरों को है। यह झूठ, धोखाभरी रियायतों और छलपूर्ण समझौतों की खुली पराजय थी। आतंक के माहौल के बाबजूद हड़ताल पूरे तौर पर कामयाब हो सकी इसका कारण था कि इसके दौरान दूसरी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे में काफी दृढ़ आत्मविश्वास आ गया था। हमारी ताकत बहुत बड़ी थी, यदि ऐसा न होता तो इस तरह की पूर्ण हड़ताल को आयोजित करने में हम कामयाब न हुए होते और उसे बहादुरी के साथ पाँच हफ्ते तक बिना एकता की भावना के नहीं खींच सकते थे; यह एकता संयुक्त मोर्चे से ही मुमकिन थी। इसके व्यापक फैलाव का दूसरा कारण यह

था कि जो ठोस मांगें रखी गयीं थीं वे सभी हिस्सों के हित में थीं, और संगठनों की भिन्नता के बावजूद सबके फायदे के लिए थीं।

जब कुछ आर्थिक लाभ तथा अन्य लाभ प्राप्त हो गए तो हड़ताल समाप्त हो गयी। वास्तव में इस हड़ताल ने 'इन्टक' के द्वारा माने गए समझौते को रद्द कर दिया। इसीलिए एक अतिरिक्त लाभ यह हुआ कि मजदूरों में फूट डालने वालों को करारी मात देकर नैतिक और राजनैतिक जीत का अहसास पाया तथा संगठन की मजबूती को बनाया।

हड़ताल की कार्रवाई के दौरान जूट-उत्पादक किसानों की माँगों, तथा जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण, जूट से बनी वस्तुओं के विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण की माँगों को प्रमुखता दी गयी थी। इन मांगों को सिर्फ औपचारिकता नहीं समझा गया था, मजदूर वर्ग की समझ को ऊँचा उठाने में इनका एक खास महत्व था।

हमारे पास इस बात की विस्तृत रिपोर्ट नहीं है कि हमने अपना संघर्ष कैसे कैसे चलाया, कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ रहीं, दूसरे संगी-साथियों ने संघर्ष किस तरह चलाया, और किस हद तक राजनैतिक कदम आगे बढ़ाए ? किन्तु यह जरूर एक स्वयं-स्वीकृत तथ्य है कि हमारी सी.आई.टी.यू. का प्रभाव और हमसे जुड़े हुए संगठनों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा है, आम मजदूरों में यह भावना बढ़ रही है कि हमारा संगठन उनकी अगुआई करता है।

हमारे यूनियन नेताओं ने एक कमजोरी को विशेष रूप से यहाँ भी महसूस किया। वह यह कि हर एक कारखाने में बड़े पैमाने पर हड़ताल कमेटियाँ नहीं बन पायीं। यह औजार जो आम मजदूर के नेतृत्व को विकसित करके केन्द्रीय फैसलों को हर मजदूर तक पहुंचाता है तथा उन्हें शिक्षित करता है, हर जगह उपयोग में नहीं लाया जा सका।

सन् १९७४ की संयुक्त हड़ताल प० बंगाल के मजदूर आन्दोलनों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम थी। इस हड़ताल ने हमारी यूनियन को और ताकत दी। इसने इन्टक के नेताओं को अलग काट दिया। हजारों साथियों ने इन्टक और उसके नेताओं के गद्दार चरित्र को व्यवहार में अपनी आँखों से देखा। इस हड़ताल ने चाहे कुछ समय के लिए ही सही, इन्टक, एटक और एच.एम.एस. के

गठबन्धन को तोड़ दिया। इस गठबन्धन ने मजदूर वर्ग के संघर्ष में सारी कठिनाइयाँ पैदा की थीं।

हड़ताल के बाद नए लोगों को शिक्षा और ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी जिससे आगे आने वाले संघर्षों में वे अगुआई कर सकें।

१९७५ की जूट हड़ताल वादाखिलाफी करने वाली सरकार के विरुद्ध एक और शानदार संघर्ष के रूप में सामने आयी। आई. जे.एम.ए. से इन्टक के नए कारनामे उजागर हो गए और यह पता लग गया कि सुधारवादी नेता लोग बेशर्मी के साथ मजदूरों को धोखा देने के लिए प्रगतिशील मुखौटा धारण किए हुए हैं।

यह जानकर कि उनका असर क्षीण हो रहा है और उनकी भरी जेबों के लिए यह खतरनाक है, कुछ इन्टक नेताओं ने हड़ताल के पक्ष में अपनी भूमिका अदा करनी शुरू कर दी। वे जानते थे कि हम संघर्ष की पूरी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारी कोई भी माँग पूरी नहीं हुई थी। फिर से एटक और एच.एमएस. ने इन्टक से गठ-जोड़ की। नवम्बर में इन्टक और ये दोनों संगठन मजदूरों से ६ जनवरी से हड़ताल पर जाने के लिए कहने लगे। हमें इस बात की जानकारी रखनी पड़ी क्योंकि पिछली बार धोखा देने के बावजूद मजदूर-एकता की दिशा में वे एक आवश्यक घटक फिर भी थे। हमने उनसे अपील की कि साथ बैठकर हम लोग एक संयुक्त संघर्ष का फैसला करें। वे इससे कन्नी काट गए। सिर्फ एक बार, अगस्त १९७४ में संयुक्त सांकेतिक हड़ताल के लिए अवश्य राजी हो गए थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने ६ जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी।

हमने ६ जनवरी की हड़ताल के आह्वान का समर्थन कर दिया। हालाँकि बाद की घटनाओं से पता लग गया कि जनवरी हड़ताल के लिए सही मौका नहीं था। संसार में जो आर्थिक गिरावट आयी थी वह अपनी चरमसीमा पर थी, अमरीकन आर्डरों में कमी हो गयी थी, लेकिन यह सोचा गया कि शायद दूसरे देशों से आर्डर मिल जाएँ और कमी पूरी हो जाए जो कि उस स्थिति का एक गलत जायजा था। सचाई यह थी कि माल काफी इकठ्ठा हो गया था और इन्टक के नेता लोग एक प्रगतिशील मुद्रा इसलिए अपना रहे थे कि आई.जे.एम.ए. को उस कठिन परिस्थिति में से उबार लिया जाय। हमारी ट्रेड यूनियनों की यह नाकामयाबी रही है कि उन्होंने

ठोस आर्थिक हालात और उद्योग के हालात को प्रायः नहीं समझा। मजदूरों को भी प्रायः नहीं बताया गया कि हड़ताल वर्ग-संघर्ष का एक हिस्सा है और उसके लिए फायदेमन्द और नुकसानदेह मौके भी होते हैं। संघर्ष की आवाज पर मजदूर लोग उस समय आसानी से भटकाए जा सकते हैं जब उनकी आर्थिक हालत गिरी हुई होती है। आखिरी मोड़ पर मजदूर को सिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हमने तथा एटक ने इन्टक नेताओं से कहा कि हड़ताल को कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाय, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़े रहे।

हालाँकि उस वक्त सभी संगठनों में पूरी एकता थी, फिर भी हड़ताल प्रतिलकू हालात में शुरू हुई। मुकाबले में खड़े रहने की ताकत इसबार मालिकों में थी। फिर भी मजदूर लोग बहादुरी से ४६ दिन तक डटे रहे। जब तक इन्टक साथ था कोई दमन नहीं हुआ, किन्तु बाद में पहले जैसा ही दमन चक्र शुरू हो गया।

उस वक्त आई.जे.एम.ए., काँग्रेस सरकार और मजदूरों के भीतर इन्टक की पूरी तरह से मिली भगत थी।

हड़ताल की समाप्ति के लिए, फिर से इन्टक, एटक और एच.एम.एस. की मिली भगत सामने आयी और हड़ताल समाप्त हो गयी। दूसरे लोग दो दिन और हड़ताल पर रहे और तब हड़ताल खत्म की। सुधारवादी इन्टक नेताओं की चालाकी भरी मिली भगत ने अत्यधिक संगठित मजदूर हड़ताल को एक ऐसे कार्य में बदल दिया जिसका तत्काल कोई लाभ नहीं हुआ। इन्टक की नई चालाकियों को अच्छी तरह समझना चाहिए जिनसे वे मजदूरों के भीतर फैले असंतोष को गलत मोड़ दे देते हैं। इस प्रकार के कदमों से किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कि वे शासक दल के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए हैं।

इसी तरह की चालाकियां सुधारवादी एटक के नेताओं ने भी अख्तियार कर ली हैं।

वास्तव में, यह हड़ताल मजदूरों के लिए बहुत ज्यादा उल्टी पड़ जाती अगर हमारी यूनियन के नेता अपने फैक्टरी के कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से आम लोगों से सम्पर्क न बनाए रखते, और उनको शुरू से ही उन कमजोरियों को न बतलाते रहते जिनके साथ वह हड़ताल शुरू हुई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि काफी तादाद में आम

मजदूरों ने इन्टक की चालाकी को परख लिया और हमें दोष का भागी नहीं ठहराया। रोजाना की गतिविधियों की रिपोर्ट कार्यकारिणी की मीटिंगों में पेश की गयी जिससे स्थानीय नेताओं को सँभालने में मदद मिली। इन कार्यों से मजदूर साथी राजनैतिक रूप से और अधिक जागरूक हुए। अब की बार अधिकतर कारखानों में व्यापक स्तर की हड़ताल-कमेटियां बनीं थीं।

कामरेड, यह बड़े अचरज की बात है कि पूरे ४६ दिन की अवधि के दौरान दूसरे औद्योगिक मजदूरों की ओर से कहीं से भी समर्थन-हड़ताल का आह्वान नहीं हुआ। जूट मजदूर अकेले ही लड़े।

ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन्टक के नेता इसके विरुद्ध थे। हालाँकि यह सही है कि हड़ताल के दौरान नेतृत्व करने वाले भिन्न संगठनों के बीच के मतभेद से अक्सर मजदूरों का हौसला पस्त होता है, और इसीलिए एकता की समझ को बनाए रखना जरूरी होता है, फिर भी, सुधारवादियों को यह मौका नहीं देना चाहिए जिससे कि खतरनाक हालात पैदा करने के लिए वे मौके का फायदा उठा ले जाएँ। अगर इन्टक के नेता लोग सहमत नहीं थे तो भी संयुक्त वामपंथी ट्रेड यूनियनों की ओर से समर्थन में हड़ताल का आह्वान आना चाहिए था। संघर्ष में जुटे हुए मजदूर साथी इस मसले पर होने वाले मतभेद को आसानी से समझ जाते।

संयुक्त मोर्चे में जो लोग सुधारवादी हैं उनकी नुकसानदेह नीतियों तथा चालाकियों पर विजय पाने के लिए बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है।

इन संघर्षों से क्या तजुर्बा हासिल हुआ? फूट डालने वाले तत्वों की कोशिशों के बावजूद सी.आई.टी.यू. यूनियन ने सबसे अधिक अहम मसलों को सही तरीकों से चुना, उन मसलों के बारे में खूब प्रचार-कार्य किया, सही तरह से तैयारियाँ की, एटक और इन्टक के पीछे चलने वाले मजदूर साथियों ने अपने नेताओं को संघर्षों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ स्थितियों में यहां तक हुआ कि उक्त यूनियनों के नेताओं ने संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया, मगर उनकी यूनियनों के मजदूर साथियों ने पूरे तौर पर एक साथ संघर्ष में हिस्सा लिया।

दिल्ली का संघर्ष

दिल्ली में कपड़ा मिलों में हड़ताल के समय सी.आई.टी.यू. ने वेतन के सही मसले को हाथ में लिया। गेट मीटिंगों और आम सभाओं के जरिए तैयारियां शुरू हुईं। एक कन्वेंशन बुलाये जिसमें एटक और इन्टक की यूनियनों को भी बुलाया। उनके बुलावे की बात को मजदूरों को व्यापक पैमाने पर बताया जिससे वे अपने नेताओं को शामिल होने के लिए निवेदन करें। इसका नतीजा यह हुआ कि इन्टक के एक हिस्से ने कन्वेशन में हिस्सा लिया। जो बाकि एटक के नेतालोग कन्वेशन में शामिल न होने के अपने निर्णय से टस से मस न हुए, मगर उनके बहुतेरे कार्यकर्त्ता उनकी नेतागीरी की परवाह न करते हुए कन्वेशन में शामिल हुए और हड़ताल की तारीख तय करायी।

कन्वेन्शन के बाद भी एकट और इन्टक के शेष नेताओं को बार बार खुला आह्वान किया कि वे भी हड़ताल में शामिल हों।

इसका नतीजा यह हुआ कि एटक के विरोध के होते हुए भी हड़ताल पूरी तौर पर कामयाब रही और एक काफी अच्छे समझौते पर दस्तखत हुए। एटक यूनियन सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त यूनियन थी और समझौते के वक़्त जब मैनेजमेंण्ट ने उस समझौते पर एटक वालों के दस्तखत करवाने चाहे तो मजदूर लोग भयंकर रूप से क्रुद्ध हो उठे, ३००० के करीब मजदूरों ने अधिकारियों को घेर लिया तथा एक आवाज में कहा कि अगर इस समझौते के बीच में कहीं भी एटक को घुसेड़ा जाएगा तो हम सब हड़ताल जारी रखेंगे। आखिरकार, मैनेजमेण्ट और सरकार दोनों को सी.आई.टी.यू. यूनियन के साथ दस्तखत करने पड़े और सी.आई.टी.यू. को मान्यता देनी पड़ी।

इसी तरह केरल में स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल के समय सी.आई.टी.यू. की पहल-कदमी में एटक तथा चार अन्य यूनियनों के बीच एकता कायम की गयी और ३-४ सितम्बर से १४½ प्रतिशत बोनस की माँग को लेकर हड़ताल शुरू हुई। सरकार ने ११½ प्रतिशत बोनस की घोषणा की थी। केरल के दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट मुख्य-मंत्री ने घोषणा की कि अगर मजदूरों को बढ़ाकर बोनस दिया गया तो वे इस्तीफा दे देंगें। काँग्रेस तथा दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट नेताओं ने एटक तथा इन्टक नेताओं पर दबाव डाला कि हड़ताल खत्म

कराओ। इस गद्दारी के बावजूद सरकार को झुकना पड़ा और बढ़े हुए बोनस के लिए समझौता करना पड़ा। मुख्यमंत्री को एकताबद्ध ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की ताकत के सामने थूक कर चाटना पड़ा और उनकी इस्तीफे की धमकी झूट साबित हुई।

तमिलनाडु में राज्यव्यापी कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल में भी सी.आई.टी.यू. ने ही पहल की और मांगों को मजदूरों के बीच ले गए। एटक, हि. म. स. और इन्टक से संयुक्त संघर्ष में आने के लिए कहा। एटक और हि. म. स. राजी हो गए, अतः उनके हाथ एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ। हड़ताल के दौरान हि.म.स. और एटक वाले चोरी छिपे मिलमालिकों और सरकार से समझौता कर रहे थे। वे लोग उनसे समझौता भी कर बैठे, तब सी.आई.टी.यू. ने उनकी गुपचुप वार्ता का पर्दाफाश मजदूरों के बीच में खुले तौर पर किया और मजदूरों के हितों के साथ किये जाने वाले दलपूर्ण सौदे को नहीं होने दिया। इस वजह से, उन्होंने सी.आई.टी यू को संघर्ष समिति से निकाल दिया। फिर भी हड़ताल जारी रही और आखिर में एक उपयुक्त समझौता हुआ। बाद में, इन्टक ने एक पर्चा जारी किया और उसे व्यापक पैमाने पर बांटा। इस पर्चे में कहा गया था कि अगर सीटू कलई न खोलती तो एटक और हि. म. स. वाले मजदूरों के साथ गद्दारी कर गए होते। मजदूर वर्ग के दबाव के सामने खड़ा न हो पाने के कारण इंटक ने आखिरी वक्त पर संघर्ष को तोड़ने की कोशिश की। १५ दिन बाद उन्होंने हड़ताल तोड़ने का नारा दिया, लेकिन उस दौरान इस प्रकार का उत्साह बना था कि इन्टक के कार्यकर्त्ताओं ने इन्टक के नेताओं की एक न सुनी और हड़ताल में शामिल हो गए। यह हड़ताल एकदम पूर्ण थी।

अखिल भारतीय एकता के लिए संघर्ष

ट्रेड यूनियनों की जो नेशनल कांउंसिल एटक, इन्टक और हि. म. स. ने सरकार की छत्रछाया में बनायी थी, वह अब बिल्कुल खत्म सी हो गयी।

दूसरी ओर यू०सी०टी० यू० ने नई दिल्ली में जुलाई १९७३ को एक कन्वेन्शन बुलाया। उसमें दो मांगों पर बल दिया गया:— **"सबको बोनस मिले तथा जरुरत पर आधारित न्यूनतम वेतन मिले"**:—इस कन्वेन्शन को बहुत बड़ी कामयाबी हांसिल हुई। इसने केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया

यह सच है कि एटक और इंटक के नेताओं ने इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी और सरकार के साथ मिली भगत चलाते रहे तथा उन्होंने वेतन आयोग की सिफारिशों में मामूली तब्दीली के साथ बहुत थोड़े पैसों पर समझौता कर लिया। फिर भी अधिकतर राज्यों में 'सबको बोनस मिले तथा जरूरतों पर आधारित न्यूनतम वेतन मिले' की माँगों को लेकर कई कन्वेशन हुए।

जरुरतों पर आधारित वेतन के नारे को मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों ने अपनाया। वेतन के ढाँचे में तब्दीली के बारे में जो बात चीत चली उसमें यह मांग मजदूरों ने प्रमुख माँग के रुप में अपने चार्टर में रखी।

पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स की यूनियनों को एकताबद्ध करने के लिए सीटू ने भरसक कोशिश की जिससे कि कर्मचारी अपनी शक्ति के बूते पर समझौते की बातचीत कर सकें। यह प्रयास सिर्फ बंगलौर क्षेत्र में ही मुमकिन हो पाया। वहाँ पर पब्लिक सेक्टर की यूनियनों ने एक सम्पर्क समिति (कोअर्डीनेशन कमेटी) संयुक्त बात चीत के उद्देश्य से बनायी।

एटक और इन्टक ने शुरुआत में ही जल्दबाज़ी की और बी. एच.ई.एल. में एक समझौता कर डाला। अन्य पब्लिक सेक्टर उद्योग के मैनेजमेन्टों ने इस समझौते को मजदूरों पर थोपना चाहा। जहाँ जहाँ सीटू की यूनियनें वार्ता में शामिल थीं, मसलन एच.एम.टी. में, वहाँ वहाँ यह हुआ कि हांलाकि बुनियादी समझौते के ढांचे में तब्दीली न करा सके, फिर भी मैनेजमेन्ट को कुछ अन्य ऊपरी हितों के बारे में मजबूर कर सके जैसे मकान के किराये भाड़े आदि के प्रतिशत को बढ़वाने आदि में।

जब रेलवे हड़ताल पर सरकार दमन करने में कामयाब हो गयी, तो मेहनतकश वर्ग पर अत्याचार करने की उसकी हिम्मत बढ़ गयी। पूरे श्रमजीवी वर्ग पर हमला हुआ। पहले एक आर्डीनेन्स जारी किया गया और बाद में उसे वेतन ज़ाम कानून के रुप में पार्लियामेन्ट में पास करा लिया गया। सब जानते हैं कि यह फैसला रेलवे हड़ताल से पहले हो चुका था। रेलवे कर्मचारियों ने इस प्रकार केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के संघर्ष को लड़ा। हमले को पराजित करने के लिए अगस्त १९७४ में वेतन-जाम विरोधी कन्वेन्शन बुलाया गया। हांलाकि एटक, इन्टक और हि.म.स. ने बाकायदा कन्वेंशन का बहिष्कार किया

अनेक छोटे कस्बों गावों में और प्रदर्शन हुए तथा गरीब जनता ने जमाखोरों के अनाज के छिपे गोदामों पर छापे मारे।

जनवादी कार्यपद्धति

ट्रेड यूनियनों में जनवादीकरण के काम को अभी भी उपेक्षित किया जा रहा है, जबकि सिर्फ़ इसी के द्वारा आम मजदूरों की समझ को ऊँचे स्तर तक विकसित किया जा सकता है। कई यूनियनों में 'नेता-अनुगामी' पद्धति के ढांचे को अभी भी अपनाया जा रहा है। यह बहुत अधिक जरूरी काम है कि जिन बहादुर लोगों को संघर्ष में झोंक दिया जाता है उनको संगठित रखा जाए, हर महत्वपूर्ण कदम पर उनकी सलाह ली जाय और उनकी सहायता से आम मजदूरों की तरह तरह की समस्याओं को लेकर जो मेहनतकशवर्ग के सामने आ रही है शिक्षा दी जाय, ये समस्याएं सिर्फ फैक्टरी की किन्हीं खास मुद्दों की न होकर ऐसी हों, जो व्यापक पैमाने पर ज्यादा जरूरी है। समूचे मेहनतकश वर्ग के सामने मुँह बाए खड़ी है। उन्हें समझाया जाय कि सरकार की आर्थिक और राजनैतिक नीतियां क्या हैं और इन जन-विरोधी नीतियों को मेहनतकशवर्ग किस तरह पराजित करने में अपनी भूमिका अदा कर सकता है ?

ट्रेड यूनियन में जनवाद के यही मायने हैं, न कि सिर्फ कार्यकारिणी समिति की औपचारिक बैठक करके सन्तुष्ट हो जाना और कुछ औपचारिक फैसलों को ले लेना। इसी जनवाद की पद्धति से हम तेजी से इस लायक हो सकेंगे कि अनगिनत कार्यकर्ताओं को मेहनककश वर्ग तथा जनवादी आन्दोलन की सेवा में लगा सकें। इसके अभाव में हमारी गतिविधियों का फैसला रूक जाता है जबकि इस समय हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर और हालात उपस्थित हुए हैं।

मजदूरों की शिक्षा की उपेक्षा

एक उदाहरण से हमारी आँख खुल जाएंगी कि हम आम मजदूरों की शिक्षा की उपेक्षा किस बुरी तरीके से करते आए हैं:— सी.आई.टी.यू. की प० बंगाल की यूनिट ने सेन्टर की सहायता से एक बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने मजदूरवर्ग के जीवन-व्यय के सूचकांक (इन्डैक्स) को बनाने में लेबर ब्यूरो शिमला की जाल-साजी का पर्दाफाश किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि अन्य सभी

फिर भी हमको बहुत बड़ा समर्थन मिला। इसमें ऐसे १४०० प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो विभिन्न यूनियनों, राज्य व केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों, ट्रेड यूनियनों से सम्बद्ध विभिन्न फडरेशनों और हि, म, स, से जुड़ी कुछेक यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते थे। हि. म. स. की कार्यकारिणी समिति के एक हिस्से ने भी कन्वेशन में हिस्सा लिया। कन्वेन्शन में यह तय हुआ कि वेतन जाम एक्ट के खिलाफ राज्य और क्षेत्रों में यथासंभव रूप में विरोधी हड़तालें, कर्बेन्शनें और प्रदर्शन किए जाएँ। २०० से उपर कन्वेन्शनें पूरे देश में हुए। यह महत्वपूर्ण बात है कि एटक के नेता, अपने मजदूर साथियों से कटजाने के डर से कुछ राज्य और क्षेत्रीय कन्वेंशन में शामिल हुए चार हड़तालें राज्य व्यापी पैमाने पर हुई—एक महाराष्ट्र, एक राजस्थान और दो केरल में। महाराष्ट्र की हड़ताल में और केरल की एक हड़ताल में एटक को भी हिस्सा लेना पड़ा।

दरअसल यह संघर्ष पूरे मेहनतकश तबके का संघर्ष है, इसमें वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी, जीवन बीमा निगम जेसी पब्लिक सैक्टर की संस्था के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी वाणिज्य संस्थानों के कर्मचारी, अध्यापक सभी केन्द्रीय सरकार की मेहनतकश-वर्ग-विरोधी, जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जुट हैं इसीलिए इस संघर्ष का बहुत अधिक महत्व है।

यह बताना जरुरी है कि सीटू इकाइयों ने हर जगह वेतनजाम विरोधी कन्वेंशन तथा संघर्षों को संगठित करने में पहल कदमी की

इस अवधि में कुछ ऐसे सवालों पर भी मेहनतकश वर्ग के लोगों ने कई संघर्ष किये हैं जिनका सम्बन्ध सीधे सीधे किसी खास उद्योग या फैक्टरी की आर्थिक माँगों से नहीं था, मसलन बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हडतालें हुई। केरल में राशन की कटौती को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल हुई; प० बँगाल में अन्य माँगों के साथ जूट पैदा करने वालों को उचित दाम दिलाने के लिए हड़ताल रही, बम्बई में बढ़ती हुई माँगों के खिलाफ हड़ताल हुई, बंगलौर में पब्लिक सेक्टर की यूनियनों तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर मूल्य-वृद्धि विरोधी-ट्रेड यूनियन कमेटी बनायी। इस कमेटी ने बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ लम्बा और व्यापक संघर्ष किया, विधान सभा के बाहर विशालतम प्रदर्शन किया, और एक दिन की विरोध-हड़ताल की। पूरे कर्नाटक राज्य में इन कार्रवाइयों का ऐसा पुरजोर असर हुआ कि पुलिस के बर्बर दमन का मुकाबला करते हुए

ट्रेड यूनियन सेन्टरों ने शामिल होकर सरकार पर दबाव डाला कि पूरे मामले की जाँच के लिए एक कमेटी बिठाई जाए। हमारी बात सही निकली और जीवन-व्यय सूचकांकों को सुधारना पड़ा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने डी.आई.आर. का इस्तेमाल करके किस तरह इन प्राप्तियों से मिलने वाले पूरे फायदे से मजदूरों को वंचित कर दिया, इसका पूरा लेखा जोखा कामरेड पान्डे की रिपोर्ट में दिया गया है। मगर इस तरह की नीचतम जालसाजी को आम मजदूरों के बीच नहीं प्रकाशित किया गया, जब कि इस मामले ने भारत सरकार को अच्छी तरह से नंगा कर दिया कि किस तरह वह अपने आकाओं के हितों की रखवाली करती आरही है। कहने का मतलब यह है कि हमारी ओर से बंगला में कोई पर्चा नहीं छापा गया और न बाँटा गया।

समझौता वार्ताओं पर जोर : आम मजदूरों की उपेक्षा

हमने पहले बताया है कि किस तरह दिल्ली कपड़ा मिल कर्मचारियों की हड़ताल पूरी तैयारी के साथ सही तरीके से नियोजित की गयी थी और इसीलिए वह कामयाब हुई और फूट डालने वाले अलग पड़ गए थे। मगर जनवरी १९७५ में जब वेननजाम के खिलाफ आम हड़ताल का आह्वान दिया गया तो यह सब तैयारी नहीं की गयी उससे पहले वाले समय में निचले स्तर से ही एकता बनाने की हर कोशिश की गयी थी, जिसकी वजह से दिल्ली की एटक हिचकिचाहट के बाद आखिर में वेतन ज़ाम विरोधी कन्वेन्शन में शामिल हो गयी। थी। कन्वेशन के वक्त भी संयुक्त मोर्चा की सही कार्यनीती अपनायी गयी थी और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव मज़दूर वर्ग के सामने रखा गया कि आम हड़ताल की तैयारी की जाए। एटक समेत सारे प्रतिनिधियों ने तैयारी कमेटी को हड़ताल की तैयारी तारीख तय करने के लिए मज़बूर किया। मगर बाद में जिस समय एटक अपने फैसले से मुकर गयी और हड़ताल का आह्वान देने से इन्कार कर दिया, उस समय हमारे कामरेडों ने कन्वेन्शन के प्रस्ताव के आधार पर उनके दोगले पन को नंगा करने का अभियान चलाने तक की तकलीफ गवारा न की। हमारी ओर से तैयारी की इस कमी की वहज से यह नतीजा निकला कि हम फूट डालने वाले तत्वों के प्रयत्नों पर

विजय प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो सके और हड़ताल हमारी आशाओं से बहुत नीचे रही।

संयुक्त संघर्षों के दौरान, निचले स्तरों पर संयुक्त समितियां बनाने में नाकामयाब होना एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ ऐसी समितियों के द्वारा ही आम मजदूरों को रोजमर्रा के हालात के बारे में खबरें देना तथा उन तमाम दगाबाजों के दांव पेंचों की कलई खोलना मुमकिन हो पाता है जो हिचकिचाहट के साथ संघर्ष में शामिल होते हैं। इसी तरह हम फूट डालने की उनकी कोशिशों को नाकामयाब बना सकते हैं। हम देख चुके हैं कि तमिलनाडु कपड़ा मिल मजदूर हड़ताल में किस तरह हमने उनके द्वारा तथा मैनेजमेंट के साथ की गयी सौदेबाजी का ठीक वक्त पर भण्डा भोड़कर मजदूर-हितों को बिकने से बचा लिया। लेकिन यह काम हमेशा हम नहीं कर पाये। कई दफा तो जब हम निचले स्तरों पर व्यापक संघर्ष-कमेटियां नहीं बना पाये तो इसका फायदा उन वर्ग-सहयोगियों को हुआ और ऐसे स्तरों पर उनका समझौता लाद दिया गया जिसकी आंदोलन की शक्ति को देखते हुए आशा भी नहीं की जा सकती थी।

वर्ग-सहयोगियों की एक और चालाकी की नीति यह रही है कि जब वे संघर्ष में हिस्सा लेने को राजी होते हैं तो वे एक शर्त लगा देते हैं कि हिस्सा लेने वाली यूनियनें मजदूरों की आम मीटिंग नहीं करें, बल्कि ऐसी मीटींगें सिर्फ संघर्ष समिति ही करे। यह बिल्कुल तय था कि संघर्ष समिति वैसी मीटींगें नहीं करेगी। इससे गद्दारी करने और बिक जाने का बढ़िया मौका मिलता है। इस तरह की पाबन्दियों के खिलाफ जमकर संघर्ष करना होगा।

इस तरह की कमियों को जल्द ही दूर किया जाना चाहिए। पिछले दो साल बहुत बड़े संघर्षों के साल रहे हैं। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, इन संघर्षों से एक एक फैक्टरी के मालिकों के खिलाफ अलग अलग चेतना की बढ़ोत्तरी बहुत अधिक हुई, और उस पूरे पूंजीपति वर्ग के खिलाफ श्रमिक वर्ग की चेतना का भी अभी उदय हुआ है, जिस पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व यह सरकार कर रही है।

सी. आई. टी. यू. और उनकी यूनियनों के द्वारा जो भूमिका अदा की गयी है, उसका नतीजा यह हुआ है कि समूचे मेहनतकशों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। हालांकि काफी सारे ऐसे हिस्सों ने

अभी अपना संगठनात्मक सम्बन्ध अन्य केन्द्रीय संगठनों से नहीं तोड़ा है। फिर भी वे सी. आई. टी. यू. को एक भरोसे लायक दोस्त तथा अपने हितों के विश्वासी अगुवा के रूप में स्वीकार करते हैं।

गाजियाबाद और फरीदाबाद की बहुत सारी यूनियनें एटक को छोड़कर सी. आई. टी. यू. के साथ आ गयी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरयाणा में भी सी. आई. टी. यू. की अनेक सारी यूनियनें काम कर रही हैं। कई दूसरी जगहों पर भी जो कार्यकर्त्ता एटक, इंटक तथा अन्य सेंटरों के साथ थे वे अपने नेताओं को छोड़कर सी. आई. टी. यू. के साथ आ गये हैं। मध्यप्रदेश के सुदूर स्थानों पर भी एकता और संघर्ष की गूंज मजदूरों के दिलों में पहुंच गयी और उन्होंने स्वतः ही यूनियनें बनाकर सी. आई. टी. यू. के साथ सम्बन्ध करा ली हैं।

यहां यह बात याद रखनी होगी कि यह सब कुछ उन हालतों के बीच हो रहा है जिनमें सरकार हम पर भयंकर हमलों पर उतारू है, गद्दारों द्वारा संगठित तोड़फोड़ की कोशिशें भी जारी हैं और पश्चिम बंगाल में अर्द्ध फासिस्टी आतंक अटूट गति से अभी तक बना हुआ है।

वास्तव में एक रास्ता तो है:—एकता और संघर्ष का, दूसरा रास्ता है—फूट डालने और संघर्षों के बर्बर दमन का। इन दोनों रास्तों के बीच एक संघर्ष—एक टकराहट तेजी से चल रही है। हम यह संघर्ष सिर्फ उन्हीं यूनियनों में नहीं देख रहे जिनकी अगुआई सीटू कर रही है, बल्कि तमाम संघर्षरत मजदूर या कर्मचारियों के संगठनों में देख रहे हैं—यह संघर्ष भारतीय बीमा निगम के कर्मचारियों में है, केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों में है, रेलवे कर्मचारियों में है। एल० आर० एस० ए० आदि में भी है। इनमें से कई एक संघर्षों में फूट डालने वालों को मुंह की खानी पड़ी। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मजबूरन एकता स्थापित करने के लिए बातचीत चलानी पड़ी है। सीटू इस बात का स्वागत करती है और तहे दिल से आशा रखती है कि वह दिन दूर नहीं जब उनमें विभिन्न स्तरों पर एकता स्थापित हो जाएगी।

संयुक्त संघर्षों को रोक पाने में असमर्थ सरकार ने निराश होकर पिछले वर्ष जनवरी में बम्बई के अन्तिम अधिवेशन में इन्टक के द्वारा सरकारी प्रस्ताव ही पास करवा दिया। प्रधानमंत्री खुद उस अधिवेशन में शामिल हुई। उस प्रस्ताव में तमाम ट्रेड यूनियनों से

कहा गया है कि देश जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगले तीन साल तक कोई हड़ताल न करें तथा मिलमालिकों से निवेदन किया है कि वे तालाबन्दी न करें।

कामरेड, हमें इस बात का अहसास रखना चाहिए कि एकता और संघर्ष हमारा रास्ता है, और फूट डालना वर्ग-सहयोग करना सरमाएदारों तथा उनके सहयोगियों का रास्ता है। किसी भी यूनिट या उद्योग में मजदूरों का हर संगठित संघर्ष उन लोगों के मुँह पर तमाचे की तरह काम करता है जिनका रास्ता वर्ग सहयोग और फूट डालने का है। ऐसे नेता लोग जब भी संयुक्त संघर्ष में शामिल होते हैं तो वे दिल में खुश नहीं होते और वे हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे कहीं संघर्ष आगे बढ़कर अपने नतीजे के चरम विन्दु तक न पहुंच जाए। इसीलिए उनकी हर ऐसी कोशिश को ना-कामयाब बनाने से हमारे एकता और संघर्ष के रास्ते को तो मजबूती हांसिल होती ही है, साथ ही हमारे संगठन को नयी ताकत भी मिलती है।

इसीलिए हमें इस रास्ते पर अडिग रहना चाहिए तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए।

इस तरह के संघर्षों ने हमें उन तमाम ट्रेड यूनियनों को संगठित करने के भारी मौके दिए हैं जो सी. आई टी यू के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें कहना होगा कि हमने इस पहलू की अपेक्षा की है। हर संघर्ष के अन्तिम नतीजे के बाद अगर हम साहसी समूहों को जुटायें और मेम्बर बनाने का काम लगन और मजबूती के साथ शुरू करें तो सी. आई. टी. यू. की संगठनात्मक हालत आज के मुकाबिल में बहुत ज्यादा हो जाए। आगामी दिनों में, कम से कम हमारे कामरेड सी. आई.टी.यू. के प्रभाव को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक गठन के मसले पर और ज्यादा ध्यान दें।

मजदूर वर्ग के संघर्षों का जनवादी आंदोलन पर असर

पिलले दो साल बड़ी उथल-पुथल वाले साल रहे। मजदूर वर्ग के अलावा लाखों लोग भयंकर दमन का मुकाबला करते हुए संघर्ष पर उतर आए। उदाहरण के लिए भारतीय बीमा निगम तथा बैंक कर्मचारी, राज्य और केन्द्रीय कर्मचारी, अध्यापक और कालेजों के प्राध्यापक, डाक्टर लोग, नर्से, विद्यार्थी, खेतिहर मजदूर, और किसान लोग।

इस अवधि में हमने जो संघर्ष छेड़े हैं, उनका निस्सन्देह जनता के व्यापक आन्दोलनों पर असर पड़ा है, अब प्रतिक्रियावादी पार्टियों की यह हिम्मत नहीं कि वे अपने उन घोर प्रतिक्रियावादी नारों को लगाएँ और जनता के सामने रखें जिनसे वे एकाधिकार पूंजीपतियों जमींदारों का पक्ष ले सकें और साम्राज्यवादियों के साथ सहयोग कर कर सकें। इस चीज को जय प्रकाश नारायण द्वारा गठित सम्पर्क कमेटी द्वारा रची गयी मांगों के अस्पष्ट चरित्र में देखा जा सकता है। जहां एक ओर कुछ ठोस मांगें हैं जैसे ज़रूरत पर आधारित न्यूनतम वेतन, भूमि सुधार के कार्यों को लागू करना, ट्रेड यूनियन का अधिकार, जनवादी अधिकार, आपतकालीन दशा (इमरजेन्सी) की समाप्ति, मीसा और डी.आई.आर. की समाप्ति आदि, तो दूसरी ओर कुछ अस्पष्ट माँगें हैं जैसे भ्रष्टाचार निवारण, आय में असमानता को दूर करना आदि।

इसी के साथ हमें यह अहसास रहना चाहिए कि इस प्रकार के संयुक्त संघर्षों के मौके दिनों दिन बढ़ रहे हैं, सरकार अपनी वर्तमान नीतियों के ढांचे के अन्दर रह कर गहराते हुए संकट से और किसी तरीके से उभर नहीं सकती; उसके सामने एक ही रास्ता है कि वह मज़दूर वर्ग और सारे मेहनतकश लोगों पर धाबा बोले। यहां तक कि सरकार की नीतियों की वजह से छोटे उद्योगपति तक इन संकट में नीचे की ओर जा रहे हैं। अतः सरकार और मिल मालिक अपने द्वारा पाली गयी इन्टक और एटक की मार्फ़त चाहे जितनी फूट डालने की कोशिश करें, वस्तुगत हालात कुछ इस तरह के हैं कि एकता और संघर्ष की आवाज बुलन्द करने का असर आम मजदूरों पर पहले से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए यह अब बहुत अहम बात है कि मजदूरों के बीच भाई चारे के रिश्ते को मजबूत बनाने के काम को बढ़ावा दें और एकता कायम करने तथा संयुक्त संघर्ष को छेड़ने के हर मौके का उपयोग करें, और इस तरह मज़दूर वर्ग में दरार डालने वालों के मन्सूबों पर पानी फेर दें।

लोक प्रिय जनवादी आन्दोलन

मजदूर वर्ग जन-आन्दोलनों के प्रति बेरूखी नहीं बरत सकता। विद्यार्थियों, अध्यापकों, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के कर्मचारियों और संघर्ष में जुटे अन्य जन हिस्सों पर होने वाले दमन के हर कुकृत्य के विरोध में मजदूर वर्ग को जबाबी कार्रवाई करनी चाहिए।

यह सोचना बिल्कुल गलत है कि मजदूर वर्ग को सिर्फ उसकी आर्थिक मांगों को लेकर ही इकट्ठा किया जा सकता है।

जहाँ मजदूर वर्ग हर जनवादी माँग का समर्थन करे और ऐसी मांगों के लिए होने वाले संघर्षों में हिस्सा लें, वहीं उसे अपने को संगठित करके आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह है, कामरेड, कि सी. आई.टी.यू. ने उन तमाम ताकतों को संगठित करने का आह्वान दिया था जो आपत्कालीन स्थिति (इमरजेन्सी) को खत्म, डी आई आर और मीसा को समाप्त करने, नागरिक स्वतंत्रा को पुनर्स्थापित करने और प० बंगाल में फैले अर्द्ध-फासिस्टी आतंक को खत्म करने की माँगों में हमारे साथ आ सकती थी। यही वजह है कि हमने उन सभी ताकतों का साथ दिया जो ६ अप्रैल की उस रेली में संगठित हुए जो आपतकालीन स्थिति, डी आई आर और मीसा के लागू रहने के खिलाफ पूरे देश में विरोध-दिवस मनाने के लिए एक जुट हुई थी। डी.आई.आर. और मीसा तथा नागरिक स्वतंत्रता के छीने जाने का सबसे बुरा शिकार मजदूर वर्ग ही हुआ है। आज यह सरकार जो एक पार्टी की तानाशाही लाने को आमादा है अपने हर विरोधी के खिलाफ इन तमाम दमनकारी हथकण्डों का इस्तेमाल करने पर उतर आयी है। यही वजह है कि संघर्ष और अधिक व्यापक हो गया है, हमें इस मौके का इस्तेमाल उन सभी ताकतों के साथ एकता बनाने के लिए करना चाहिए जो इस हमले का शिकार हैं और तमाम ऐसे लोगों को उन दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ संगठित करने की जीतोड़ कोशिश करनी चाहिए। इस दमन की नीति से पूरा राज्य पुलिस राज बन चुका है।

कामरेड, जनता के सभी हिस्सों की हलचल तथा जनता के आन्दोलनों के सन्दर्भ में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम विकल्प की नीतियों के लिए संघर्ष को न सिर्फ अहमियत दें, बल्कि इस संघर्ष को अनवरत और आवश्यक भी समझें।

एकता का मंच

इसी पृष्ठभूमि में, अगस्त १९७४ को वेतनजाम विरोधी कान्फ्रेंस का मंच इस संघर्ष का एक अगला कदम है। इस मंच ने निर्विरोध रूप से उस कन्वेन्शन में जिसमें ट्रेड यूनियनों का वहुत व्यापक प्रतिनिधित्व था जो प्रस्ताव पास किया वह हमें ठोस प्रोग्राम तथा विकल्प की ऐसी नीतियां प्रदान करता है जिनका अमल ही इस देश को जनवादी जिन्दगी की ओर ले जाएगा और समाजवाद के लिये रास्ता

तैयार करेगा। यहां विकल्प के उस प्रोग्राम को दोहराना जरूरी है। वह इस प्रकार है :-

१ तमाम ज़माखोरी का जमा और खुला हुआ अनाज तथा जरुरियात की चीजों के स्टाक को बड़े बड़े जमीदारों, थोक विक्रेताओं से अपने अधिकार में ले लिया जाय तथा हमारी जनता कमेटियों की देखभाल के अन्तर्गत उनके सरकारी वितरण की व्यवस्था हो।

२ बड़े बड़े जमीदारों के पास से बाजार में विक्रय के लिए संचित सारा अनाज, थोक व्यापार के लिए सरकार द्वारा ले लिया जाए, जरुरत की अन्य चीज़ें उनके उत्पादन कर्त्ताओं से ले लिये जाएँ तथा जनता से कमेटियों की देखभाल में कन्ट्रोल भाव पर उनके समान वितरण की सरकारी व्यवस्था हो।

३ ऊंची रुकम के करेन्सी नोटों को रद्द कर दिया जाए तथा एक सीमा से ऊपर बैंक में जमा धन ज़ब्त कर लिया जाए।

५ आम उपयोग की चीज़ों पर से एक्साइज तथा दूसरी डयूटियाँ या तो खत्म कर दी जाएँ या उनमें भारी कटौती कर दी जाएं तथा घाटे के बज़ट की प्रथा समाप्त हो।

५ देशी और विदेशी एकाधिकार पूंजीपति घरानों के व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले ले।

६ सारे विदेशी कर्ज़े की अदायगी पर पाबन्दी लगा दी जाए।

७ सारी छोटी बड़ी बन्द फैक्टरियाँ खोली जाएँ तथा उनकी क्षमता का भरपूर उपभोग हो।

८ देश भर में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिये तथा बड़े ज़मींदारों से जमीन को खेतिहर मज़दूरों, गरीब किसानों की कमेटियों की देखरेख में उनके बीच बाँटने के लिए कदम उठाएँ जाएँ।

९ गैर संगठित और खेती के सैक्टर में लगे मज़दूरों के लिए समान वेतन मान निर्धारित किये जाएँ और उन्हें लागू किया जाए।

१० सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार और अफसर शाही खत्म की जाए।

११ वेतन जाम के सारे कदम तुरन्त वापस लिये जाएं तथा जरूरतों पर आधारित नयुन्तम वेतन की माँग को मंजूर किया जाए।

१२ मजदूर वर्ग-विरोधी नीतियों तथा दमनकारी तरीकों और कानून तथा दण्डित करने की कार्रवाईयों का खात्मा हो और जनवादी आधार पर औद्योगिक सम्बंधों की स्थापना की जाए।

१३ सबको नौकरी मिले या बेरोजगारी का भत्ता मिले ।

इससे स्पष्ट है कि यह प्रोग्राम ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, असमानता को कम किया जा सकता है, जनता के लिए जीवन की न्यूनतम हालातों को पैदा किया जा सकता है, बेरोजगारी घटाई जा सकती है, विकास के लिए सभी मौजूदा साधनों का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है और देश यहाँ की जनता के लिए एक समृद्ध जीवन निर्माण करने की ओर अग्रसर हो सकता है ।

उक्त कन्वेंशन में बने इस मंच ने इस प्रोग्राम का प्रचार करने और मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का मौका सिर्फ सी.आई.टी.यू. के मंच से ही नहीं दिया बल्कि संयुक्त ट्रेड यूनियनों के मंचों से भी दिया है ।

वेतनजाम के खिलाफ जो कन्वेन्शन और रैली हुई उनमें इस बात को स्वीकार किया कि विकल्प के इस प्रोग्राम का प्रचार संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ है । मजदूर वर्ग पर होने वाले हर हमले के खिलाफ लड़ते वक्त चाहे वह वेतनजाम हो, या छँटनी, या 'ले-आँफ' आदि हो, यह निहायत जरूरी है कि मजदूर-वर्ग के सामने यह बात लाई जाए कि इस सरकार की मौजूदा आधारभूत नीतियों के ढांचे के भीतर रहते हुए जनता के कष्टों से छुटकारा नहीं मिल सकता । जिस मंच को ट्रेड यूनियनों ने बनाया है सिर्फ वही सच्चा जनवादी विकल्प दे सकता है बशर्ते लोग आगे बढ़े । इसी के द्वारा देश को नव-उपनिवेशवाद के खतरों से बचाया जा सकता है ।

इस तरह से आज इस प्रोग्राम के आधार पर समूचे मजदूर वर्ग व कर्मचारियों को व्यापक स्तर पर संगठीत करना सबसे अधिक जरूरी हो गया है, जिससे कि लोग जो भाववाद की आग लेकर मोजूदा हालत से तंग आकर गलियों में निकल आए हैं और आगे बढ़ रहें हैं, कहीं उन ताकतों के द्वारा ठग न लिए जाएँ और भटका न दिए जाएँ जो इस जन-आन्दोलन का फायदा उठाना चाहती हैं, और जो आर्थिकस्तर पर तथा समाज के स्तर पर यथा स्थिति बनाए रखने को आमादा हैं ।

इसके अतिरिक्त, मजदूरवर्ग को यह अहसास करा देना सबसे जरूरी काम हो गया है कि वह अपने बढ़े हुए हिस्से के द्वारा खेतिहर मजदूर और किसानों को संगठित करें । इस दिशा में किए गए प्रयत्नों का कुछ नतीजा निकला है । मगर वह अभी संतोषजनक

नहीं है। एकजुट होकर समूचे देश के स्तर पर यह काम होना चाहिए, जिससे किसानों और खेतिहर मजदूरों का विशाल समूह इस संघर्ष में हिस्सा ले सके।

इसके अलावा, अनाज और दूसरी उपयोग की चीज़ों की बढ़ती कीमतों तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी ने हमें मजदूरवर्ग को शिक्षित करने का मौका दिया है कि मजदूर वर्ग की समस्याएं तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि किसान और आम आदमी के ऊपर जमींदारों और थोक व्यापारियों के शिकंजे पर चोट नहीं होती। यह बहुत ही जरूरी है कि मजदूर वर्ग किसानों और खेतिहर मजदूरों की मांगों की आवाज उठाए और सक्रिय रूप से उनके आन्दोलनों का समर्थन करें।

यहाँ मैं यह भी बताना चाहुँगा कि देश के अधिकतर भाग में हमारे संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों में बहुत ही कम दिलचस्पी दिखाई है। वीयतनाम और कम्बोडिया की जनता की ऐतिहासिक जीत पर खुशीयाँ मनाते हुए हजारों की तादाद में मजदूर वर्ग को सड़कों पर निकल आना चाहिए था। अमरीकी साम्राज्यवाद पर जो करारी चोट हुई है उससे हमारे मजदूरवर्ग और मेहनतकश इन्सान को इस उपमहाद्विप में अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा किए जाने वाले षड्यन्त्रों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करने की प्रेरणा लेनी चाहिए।

साम्राज्यवाद चारों ओर से संकट-ग्रस्त हो रहा है और हमारे देश के लोग भी विकसित देशों की जनता और मजदूरवर्ग के कदम से कदम मिलाकर आदमी के द्वारा आदमी के शोषण को खत्म करने की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। सर्वहारा वर्ग में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना पैदा करने की इस कमजोरी को तेजी के साथ दूर करना होगा।

इतना और कह दूँ कि वर्ग संघर्ष को तेज करना हमारा सबसे जरूरी काम है। यह संघर्ष सिर्फ आर्थिक मांगों के संकुचित दायरे में न होकर सर्वांगीण विकास के बारे में होना चाहिए। मजदूरवर्ग अपने इस कर्त्तव्य को निभाकर हीसारी मेहनतकश जनता की अगुआई करने के लायक हो सकेगा और जनवाद की लड़ाई का हिरावल बन सकेगा तथा गद्दारों से आन्दोलन की रक्षा कर पाएगा।

अतएव, इस तीसरी कान्फ्रेन्स में हम सब मिलकर, प्रतिज्ञा करेंगे कि इस संघर्ष के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, इसे हम बिना विचलित हुए और आगे ले जाएँगे।